Discover your divinity with us
A/C Showroom
ज्ञान गंगा ॐ मूर्ति माला केन्द्र
उजाला भवन स्टेशन रोड, दुर्ग
0788-4030383, 3293199
भगवान के वस्त्र, श्रृंगार मूर्तियां एवं समस्त पूजन सामग्री संगमरमर व पीतल की मूर्तियां राशि रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...
रायपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर से प्रकाशित

समय दर्शन

ESTD : Since 2011

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर
निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

श्री
दुर्ग शहर में सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य
पं. एम.पी. शर्मा/
मो. 8109922001
फीस 251/- मात्र
पता:- श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय सिकोला भाठा, सब्जी मार्केट के सामने, धमधा नाका, दुर्ग

वर्ष 15, अंक 115 | पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रूपये | दुर्ग, शुक्रवार 13 मार्च 2026 | www.samaydarshan.in

संक्षिप्त समाचार

बीएसएफ-पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में सीमा पार से आई 2किलो हेरोइन बरामद, कीमत 12 करोड़ रुपए

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान नशे की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। ड्रोन के जरिए गिराई गई इस हेरोइन का वजन करीब 2 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 12 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, सीमा पर संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की सूचना मिलने के बाद ब्रस्स और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। इलाके की घेराबंदी कर रात भर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान जवानों को सीमावर्ती इलाके के खेतों में एक संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ। जब पैकेट को खोला गया, तो उसमें उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन भरी हुई थी। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण नार्को-टेररिज्म के इस बड़े प्रयास को विफल कर दिया गया। पिछले कुछ समय से सीमा पार बैठे तस्करों और आतंकियों ने हथियारों और नशे की तस्करी के लिए ड्रोन तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जब्त की गई हेरोइन को कश्मीर के आंतरिक इलाकों में सप्लाई किया जाना था। फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सीमा के इस तरफ इस खेप को रिसीव करने वाला कौन था।

अजय भादू ने आईएसपीआई 2026 का उद्घाटन किया, भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट और टिकाऊ पैकेजिंग पर दिया जोर

नई दिल्ली। भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) द्वारा आज नई दिल्ली में पैकेजिंग उद्योग के छठे अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हूस्क्क्ष 2026 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री प्रतिनिधियों, अकादमिक विशेषज्ञों, रिसर्चर्स एवं भारत और विदेश से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री अजय भादू द्वारा किया गया। इस वर्ष सम्मेलन का विषय फ्पैकेजिंग 5स्ह्व ङ्क सेफ, सिक्योर, स्टैंडर्डाइज्ड, स्मार्ट, सस्टेनेबल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसफ्र रखा गया है। इस विषय के माध्यम से पैकेजिंग सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी के उपयोग, प्रोडक्ट सेफ्टी, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने, स्टैंडर्डाइजेशन एवं एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर भारतीय पैकेजिंग संस्थान के निदेशक श्री आर. के. मिश्रा ने उपस्थित अतिथियों, विशेषज्ञों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। इसके बाद आईआईपी दिल्ली के अतिरिक्त निदेशक एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रो. (डॉ.) तनवीर आलम ने सम्मेलन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए पैकेजिंग 5स्ह्व की अवधारणा एवं इसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर आईआईपी दिल्ली में एक डिज़ाइन लैब का उद्घाटन भी किया गया तथा संस्थान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (स्श्व) पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल पैकेजिंग सेक्टर में इनोवेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रिसर्च, ट्रेनिंग और इंडस्ट्री पार्टनरशिप के माध्यम से भारतीय पैकेजिंग संस्थान देश में पैकेजिंग क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को यह सुनिश्चित करने में सहयोग कर रहा है कि भारतीय उत्पाद ग्लोबल मार्केट्स तक सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच सकें। हूस्क्क्ष 2026 के दौरान होने वाली चर्चाओं और सहयोग से पैकेजिंग सेक्टर में इनोवेशन को और गति मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी।

खेल-खेल में बच्चों ने डाला पानी, तो सनके युवक ने 5 मासूमों पर उड़ेल दिया खौलता तेल; रूह कंपा देगी यह वारदात

उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक तेरहवीं के कार्यक्रम के दौरान हुई मामूली सी बात पर एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। खेल रहे बच्चों द्वारा गलती से पानी डाल दिए जाने पर इस शख्स ने गुस्से में अपना आपा इस कदर खोया कि पांच मासूम बच्चों पर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया। इस अमानवीय और दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई। गंभीर रूप से झुलसे सभी बच्चों को तुरंत लखनऊ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।

मुख्यमंत्री ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का किया शुभारंभ

बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री साय

रायपुर (समय दर्शन। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय स्थित सभागार से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया और अधिक से अधिक लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2 हजार 931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की

सब्सिडी भी अंतरित की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बिजली आज हमारी मूलभूत जरूरतों में शामिल हो चुकी है और इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कई परिवार आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे सरचार्ज के कारण बकाया राशि बढ़ जाती है और पूरा भुगतान करना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाधान योजना शुरू की है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान योजना के माध्यम से लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले प्रदेश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की गई है। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के लगभग 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जिससे आजादी के बाद से अंधेरे में रहे गांव भी रोशन हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हमारे अपने संसाधनों से लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की इस परेशानी को समझते हुए समाधान योजना लागू की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति प्रदेश में लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है और अब तक लगभग 36 हजार लोग इससे जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वेंडर के रूप में कार्य किया जाना एक सकारात्मक पहल है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बिजली की बचत करने और घरेलू बिजली के अनावश्यक उपयोग से बचने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को समाधान योजना के लिए बधाई देते हुए निर्देश दिए कि शिविर लगाकर और व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को समाधान योजना से जोड़ा जाए।

उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक जमा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है।

ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ सैलरी के आधार पर नहीं होगा निर्धारण

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के नॉन-क्रीमी लेयर (एनसीएल) के निर्धारण में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 11 मार्च को कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्रीमी लेयर का फैसला सिर्फ माता-पिता की सैलरी या आय पर आधारित नहीं किया जा सकता, बल्कि 1993 के मूल दिशानिर्देशों के अनुसार पद की स्थिति और अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर माता-पिता सरकारी नौकरी में ग्रुप सी या ग्रुप डी में हैं, तो उनकी सैलरी को क्रीमी लेयर तय करने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही कृषि से होने वाली आय को भी पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। क्रीमी लेयर तय करने के लिए केवल 'अन्य स्रोतों' (जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, किराया आदि) से परिवार की कुल आय तीन लगातार वर्षों में औसतन 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। इस फैसले में कोर्ट ने 2004 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उस पत्र के पैरा 9 को अमान्य घोषित कर दिया है, जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू कर्मचारियों की सैलरी को क्रीमी लेयर में शामिल करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और प्राइवेट/पीएसयू कर्मचारियों के बच्चों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। जब तक पीएसयू या प्राइवेट पोस्ट की सरकारी ग्रुप थर्ड या फोर्थ के साथ समकक्षता तय नहीं हो जाती, तब तक केवल 1993 के मूल आदेश (ओएम) लागू रहेंगे।

यह फैसला उन हजारों ओबीसी उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें पहले सैलरी या अन्य गलत व्याख्या के कारण क्रीमी लेयर मानकर आरक्षण से वंचित रखा गया था। ऐसे लोग सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन सही कैडर या पद में नहीं पहुंच पाए।

एलपीजी गैस संकट पर पीएम मोदी का कड़ा रुख, मंत्रियों को दिए सख्त निर्देश

एलपीजी गैस संकट पर पीएम मोदी का कड़ा रुख, मंत्रियों को दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान में चल रहे युद्ध के कारण देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत और लंबी लाइनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी है। गुरुवार को अपने मंत्रियों के साथ हुई एक अहम बैठक में पीएम मोदी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग इस संकट का फायदा उठाकर देश में घबराहट और पैनिक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने मंत्रियों से स्पष्ट कहा कि वे सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव रहें और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे किसी भी प्रोपेगेंडा या भ्रामक प्रचार का आक्रामक तरीके से, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दें।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों और अपनी कैबिनेट को आश्वस्त किया है कि इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत की तैयारियां बहुत पुख्ता हैं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसका असर सिर्फ किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। हालांकि, हमारे पड़ोसी और दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में भारत इस संभावित संकट का सामना करने के लिए कहीं अधिक बेहतर और मजबूत स्थिति में है। इससे पहले बुधवार को भी तमिलनाडु में एनडीए की एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कमर्शियल एलपीजी की कमी से प्रभावित होटल क्षेत्र का जिक्र करते हुए जनता से पैनिक न करने और केवल प्रमाणित जानकारी ही साझा करने की अपील की थी।

एक तरफ देश के अंदर गैस संकट को लेकर सरकार मुस्तैद है, तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारत को एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल हुई है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ह्लह्म्ड्डद्बह्ल शद्घ ॥शह्म्द्वह्व5) के अहम समुद्री मार्ग से अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही रोकने और बाधित करने की कोशिशों के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से उच्च स्तरीय वार्ता की। इस कूटनीतिक बातचीत का शानदार नतीजा निकला है और ईरान भारत के लिए इस रास्ते को खोलने पर राजी हो गया है। समझौते के तहत, ईरान अब भारतीय झंडे वाले टैंकरों को वहां से बिना किसी रोक-टोक के गुजरने देगा।

शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस दिन से शुरू हो रही है आदि कैलाश यात्रा, जाने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड में भगवान शिव के पवित्र धाम आदि कैलाश की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर मौसम ने पूरा साथ दिया, तो 1 मई से इस साल की आदि कैलाश यात्रा का भव्य आगाज हो जाएगा। प्रशासन की तैयारियों के मुताबिक, अप्रैल के आखिरी सप्ताह से ही यात्रा के लिए जरूरी 'इनर लाइन परमिट' जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पिछले साल इस पवित्र यात्रा में 30 हजार से ज्यादा शिव भक्तों ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया था, और इस बार श्रद्धालुओं की इस संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आदि कैलाश उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में स्थित बेहद खूबसूरत और दुर्गम व्यास घाटी में मौजूद है। अत्यधिक ऊंचाई वाले इस इलाके में नवंबर से लेकर मार्च तक भारी बर्फबारी होती है, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से इस यात्रा को सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से रोक दिया जाता है। अब बर्फ पिघलने के साथ ही प्रशासन ने एक बार फिर से इस कठिन लेकिन आस्था से भरी यात्रा को शुरू करने की पूरी योजना बना ली है।

मुंबई मेट्रो, बीएसई, हाईकोर्ट और विधानभवन को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर पुलिस

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और बॉम्बे हाईकोर्ट समेत मुंबई में कई जगहों पर बम विस्फोट की धमकी से दहशत फैल गई। ईमेल के जरिए अलग-अलग ठिकानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।

मुंबई पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विधानभवन और हाईकोर्ट को धमकी भरे ईमेल मिले। इसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। संबंधित पुलिस स्टेशन पर जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की गई। बीएसई के एक प्रवक्ता ने कहा, हमें धमकी भरा ईमेल

मिला है। सावधानी के तौर पर जरूरी इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं और हम संबंधित सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। विधानभवन को भेजे गए ईमेल में लिखा गया, विधान भवन में बम रखा गया है। इसके बाद, सुरक्षा के मद्देनजर पूरा विधानसभा परिसर खाली करा दिया गया। पत्रकारों और कर्मचारियों को बाहर भेज दिया गया।बम स्क्वॉड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरी तरह सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉग स्क्वॉड भी बुलाया गया है ताकि किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री जल्दी से जल्दी मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई बम या विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन खोज पूरी तरह संतोषजनक न होने तक जारी रहेगी। इसके बाद मुंबई मेट्रो और बैंकों को धमकी भरे ईमेल मिले। हालांकि, अभी तक मुंबई में किसी भी जगह से कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की जानकारी सामने नहीं आई।

महाराष्ट्र विधान परिषद के चेयरमैन राम शिंदे ने भी बम विस्फोट की धमकियों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) को सुबह 6.57 बजे एक ईमेल भेजा गया था। उन्होंने कहा, चूंकि बजट सत्र चल रहा है, इसलिए ईमेल में खासतौर पर बम का इस्तेमाल करके हमले की धमकी दी गई थी। धमकी में मुंबई में चार हाई-प्रोफाइल टारगेट की पहचान की गई थी, जिनमें विधानभवन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई मेट्रो शामिल हैं।

शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया है कि विधानसभा, मेट्रो और स्टॉक एक्सचेंज को धमकी देने वाला ईमेल खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों से जुड़ा हो सकता है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि भेजने वाले ने इन जगहों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों और बमों के इस्तेमाल का साफ तौर पर जिक्र किया है। फिलहाल, मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस की छानबीन चल रही है।

किरण देव ने विधानसभा में जताया रोष

4 साल बीते, टेंडर के बाद भी झीरम व कांदानार के बीच नहीं बनी सड़क

समय दर्शन

रायपुर। विधानसभा में आज भाजपा विधायक किरण देव ने रोष जताते हुए कहा कि 4 साल का समय गुजर जाने के बाद भी झीरम-कांदानार के बीच की सड़क नहीं बनी। दो माह बचे हैं, काम शुरु नहीं हुआ तो हर बार की तरह इस बार भी निर्माणाधीन सड़क की मुरुम मिट्टी बह जाएगी।

प्रश्नकाल में किरण देव का सवाल था कि क्या एमएमजीएसवाई योजना अंतर्गत झीरम व्हाया एलेंगनार-उरकापाल कांदानार सड़क के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? सड़क की कुल लंबाई एवं संभावित व्यय कितना था? प्रशासकीय स्वीकृति एवं टेंडर कब जारी किया गया? कार्यादेश किस कंपनी/फर्म को प्रदान किया गया? क्या निर्माण हेतु तैयार डीपीआर में आवश्यक समस्त प्रस्ताव सम्मिलित नहीं हो सके थे? यदि हां तो कौन-कौन से कार्य के प्रस्ताव किन कारणों से सम्मिलित नहीं हो सके? कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण

विकास) विजय शर्मा की ओर से जवाब आया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत झीरम व्हाया एलेंगनार-उरकापाल कांदानार सड़क के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति 10 जनवरी 2023 को प्रदान की गई है। सड़क की कुल लंबाई 18 किलोमीटर एवं संभावित व्यय रूपये 14 करोड़ 60 लाख 60 हजार था। प्रशासकीय स्वीकृति टेंडर 30 जनवरी 2023 को जारी किया गया। कार्यादेश विनोद सिंह राठौर, मेन रोड मस्तानपारा सुकमा (जिला सुकमा) को प्रदान किया गया है। निर्माण हेतु तैयार डीपीआर में आवश्यक समस्त प्रस्ताव सम्मिलित नहीं हो सके थे। उक्त सड़क नक्सल प्रभावित झीरम क्षेत्र को कोलेंग क्षेत्र से जोड़ती है। उक्त सड़क दुर्गम पहाड़ी एवं घोर नक्सली क्षेत्र होने के कारण पूर्व में विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना संभव नहीं था। साथ ही उक्त सड़क आरक्षित वन भूमि में होने के कारण एलाईनमेंट में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण सीसी सड़क, टो-वॉल, नाली, पुल-पुलियों एवं घाट कटिंग के अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हुई। अतिरिक्त शेष कार्य हेतु राशि 5 करोड़ 59 लाख 69 हजार की स्वीकृति जिला खनिज न्यास निधि मद जिला सुकमा से प्रदान की गई है। मूल स्वीकृति झीरम से कांदानार तक 18 किलोमीटर बीटी सतह तक स्वीकृत थी। स्थल में परिवर्तन एवं अन्य कारणों की वजह से उक्त राशि में 18 किमी का कार्य संभव नहीं था। इसलिए मूल स्वीकृति अनुसार पूरी लंबाई में जीएसबी स्तर तक कार्य किया गया। झीरम से एलेंगनार तक 0 किमी. से 11.10 किमी में बी.टी. एवं अन्य कार्य प्रस्तावित किये गये। शेष लंबाई में एलेंगनार उरकापाल से कांदानार तक 11.10 किमी से 18 किलोमीटर के लिए जीएसबी स्तर से उपर के कार्य एवं पुल-पुलिया, रिटेनिंग वॉल एवं अन्य कार्यों की स्वीकृति जिला खनिज न्यास निधि मद जिला सुकमा से प्राप्त की गई। मूल स्वीकृति 10 जनवरी 2023 को 14 करोड़ 60 लाख 60 हजार की थी। अतिरिक्त कार्य हेतु 18 जनवरी 2025 को 5 करोड़ 59 हजार 69 हजार की स्वीकृति प्राप्त की गई। भाग ख हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर निविदा आमंत्रित की गई है। कार्यादेश रामशरण सिंह प्रोजेक्ट, एलएलपी, शांति नगर जिला सुकमा को प्रदान किया गया है। अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि 20 नवम्बर 2026 तक निर्धारित है। कार्य 20 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है। किरण देव ने पूछा कि सर्वे नहीं हुआ तो टेंडर कैसे जारी हो गया। 3 वर्षों में कितना काम हुआ और ठेकेदार को कितना भुगतान हुआ।

(शेष पृष्ठ 3 पर)।

स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों पर अधिकारी देते हैं गलत जानकारी

विधानसभा में आज भाजपा विधायक सुश्री लता उसेंडी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यक्रमों पर संबंधित विभाग के अधिकारी लगातार गलत जानकारी देते आ रहे हैं। उन्हें बराबर संरक्षण मिलते रहा है। प्रश्नकाल के दौरान लता उसेंडी का सवाल था कि कोंडागांव जिले में वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं? सेटअप अनुसार कितने स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं और कितने रिक्त हैं? कितने नए प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने हेतु शासन को पत्र/प्रस्ताव प्रेषित है? वर्तमान में जिले में विभाग अंतर्गत ऐसे कितने केंद्र हैं जहां पर भवन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है? क्या उस हेतु शासन को कोई प्रस्ताव या पत्र प्राप्त हुआ है? कोडागांव जिले में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत विगत 2 वर्षों में कितने शासकीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्या उनका किसी भी प्रकार का देयक लंबित है? यदि हां तो उनका कब तक भुगतान कर दिया जाएगा? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की ओर से जवाब आया कि कोण्डागांव जिले अंतर्गत 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 173 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। जिले अंतर्गत वर्ष 2025-26 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोण्डागांव के व्दारा 3 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। विभाग व्दारा कोण्डागांव जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोलावण्ड की स्थापना हेतु पदों की स्वीकृति वर्ष 2025-26 में प्रदान की गई है। शेष प्रस्ताव पर मापदण्ड/नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में जिले अंतर्गत 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता है। 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के संबंध में जिला कोण्डागांव से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 1157 शासकीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें किसी भी प्रकार का देयक लंबित नहीं है। लता उसेन्डी ने कहा कि आपके जवाब में आया है कि किसी भी तरह का भुगतान शेष नहीं है, जबकि कार्यक्रमों का कहीं पर भुगतान हुआ है, कहीं पर नहीं। इसके तथ्य मेरे पास हैं। मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम हुए हैं। कुछ हॉस्पिटल के भीतर और कुछ बाहर टेंट लगाकर, जिनका 4 लाख 57 हजार का भुगतान किया गया है। लता उसेंडी ने कहा कि मौखिक निर्देश पर कार्यक्रम हुए और मौखिक निर्देश पर भुगतान भी हो गया। कहीं पर बिल का भुगतान हो जाता है तो कहीं पर नहीं होता। या तो पूरे बिलों का भुगतान करवाएं या बिलकुल नहीं करवाएं। लिखित जवाब में आया है कि निरंक है, जबकि निरंक नहीं है। अधिकारी लगातार गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्हें संरक्षण देते आ रहे हैं। हमें अपनी बात रखने के लिए विधानसभा सत्र का इंतजार करना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्क ऑर्डर जारी हुआ और भुगतान नहीं हुआ हो, मुझे बताएं भुगतान करवाऊंगा। मौखिक तौर पर कहेंगे तो भी करवाऊंगा। लता उसेंडी ने कहा कि पिछले सत्र में भी मैंने सवाल लगाया था तो आपने कहा था गलत जानकारी देने वालों को नोटिस देंगे। नौ माह निकल गए, नोटिस का क्या हुआ? दोषी अधिकारियों को लेकर जो तथ्य मैंने दिए थे वह आपके पास हैं। मंत्री ने कहा कि उस संबंध में कार्यवाही हुई है। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि सदन में जवाब सही नहीं आ रहा है। हर बार गलत जवाब आता है।

खबर-खास

फोरलेन सड़क पर गैरेज का कब्जा, आवागमन में हो रही भारी परेशानी

पाटन (समय दर्शन)। दुर्ग-पाटन मार्ग पर सेलूद और पाटन के बीच फोरलेन सड़क पर अवैध रूप से संचालित गैरेज और सड़क पर खड़े भारी वाहनों के कारण आवागमन में गंभीर परेशानी हो रही है। हाइवा और अन्य बड़े वाहनों को आधी सड़क पर खड़ा कर उनकी मरम्मत की जा रही है, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा बाधित हो रहा है और वाहन चालकों को ओवरटेक करने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। विशेष रूप से सेलूद में राइस मिल के सामने पाटन रोड पर स्थिति और अधिक खराब हो गई है। यहां सड़क के किनारे भारी वाहनों को खड़ा कर मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार जाम जैसी स्थिति बन रही है और दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है।

वहीं पाटन नगर में स्टेट बैंक से लेकर बीएसएनएल ऑफिस तक सड़क के आधे हिस्से पर गैरेज संचालकों का कब्जा बना हुआ है। सड़क किनारे खड़े ट्रक, हाइवा और अन्य वाहनों के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है तथा आम लोगों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन लोकनिर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर हो रहे इस अतिक्रमण को हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए, ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम हो और लोगों को राहत मिल सके।

झेरिया धोबी समाज पाटन राज का वार्षिक अधिवेशन ग्राम लोहरसी (तर्रा) में 15 मार्च को होगा

पाटन (समय दर्शन)। झेरिया धोबी समाज पाटन राज का वार्षिक अधिवेशन ग्राम लोहरसी (तर्रा) में 15 मार्च को कलश यात्रा नगर भ्रमण के साथ आरम्भ होगा। जिसमें मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक पाटन श्री विष्णु निर्मलकर जी की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि श्री देवेंद्र चंद्रवंशी जी जिला पंचायत सदस्य उत्तम बघेल जी जनपद सदस्य राकेश साहू जी सरपंच ग्राम लोहरसी एवं सामाजिक अतिथियों की उपस्थिति में स्वागत अतिथि उदबोधन एवं सामाजिक विषयों पर चर्चा पश्चात भोजन काल युवक युवती परिचय सम्मेलन समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र यादव जी स्कूल शिक्षा मंत्री होंगे अति विशिष्ट अतिथि श्री तुलसी कौशिक जी निज सहायक मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अध्यक्षता श्री पोसु राम निर्मलकर जी करेंगे अतिथियों के स्वागत उदबोधन पश्चात प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं वरिष्ठ समाज प्रमुखों का सम्मान एवं समापन समारोह होगा उक्त जानकारी डॉ धर्मेन्द्र निर्मल अध्यक्ष झेरिया धोबी समाज पाटन राज मीडिया प्रभारी योगेश निर्मलकर ने दी है।

फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झीट स्वास्थ्य केंद्र में कार्यशाला आयोजित

पाटन (समय दर्शन)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के निर्देशानुसार तथा खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. भुवनेश्वर कठौतिया के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय फाइलेरिया (हाथी पांव) उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत रुग्णता प्रबंधन एवं विकलांगता की रोकथाम को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झीट में कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में मरीजों को बेहतर स्वच्छता, रख-रखाव तथा प्रभावित अंगों की साफ-सफाई के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान मरीजों को टब, बाल्टी, टॉवेल, मग और साबुन भी वितरित किए गए, ताकि वे नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रख सकें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झीट के अंतर्गत कुल 9 मरीजों की लाइन लिस्ट तैयार की गई थी। एमएमडीपी प्रशिक्षित कमल नारायण तिवारी (आरएचओ) द्वारा मरीजों को अंगों की सफाई, देखभाल तथा स्वच्छता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बी.एल. वर्मा (बीईटीओ), जे.आर. मार्कण्डेय, मधु देवांगन, मधुलता लाल, प्रेमराजकुमारी एवं सुपरवाइजर कपिश भोसले सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

कवर्धा वनमंडल में आईजीएनएफए देहरादून के 33 प्रोबेशनर्स अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण भ्रमण

कवर्धा (समय दर्शन)। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के वर्ष 2025-27 बैच के 33 भारतीय वन सेवा के प्रोबेशनर्स अधिकारियों का छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत कवर्धा वनमंडल में Soil & Water Conservation Measures and Watershed Management E&ercise विषय पर दिनांक 11 से 12 मार्च 2026 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण भ्रमण आयोजित किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त प्रोबेशनर्स अधिकारियों को चिन्हांकित 04 नालों के लिए पृथक-पृथक 04 समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह द्वारा संबंधित नाले के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए पीपीआर/डीपीआर तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एनआरएम इंजीनियर तथा कवर्धा वनमंडल के तकनीकी सहायकों सहित समूहवार अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। दिनांक 11 मार्च 2026 को कवर्धा वनमंडल के सभागार में श्रीमती अजीता लॉगजम (भा.व.से. 2012), निखिल अग्रवाल, वनमंडलाधिकारी, कवर्धा, नवनीत नायक, एनआरएम इंजीनियर, जीआईएस एक्सपर्ट, कैम्पा, समस्त उपवनमंडलाधिकारी तथा अधीक्षक भोरमदेव अभ्यारण्य की उपस्थिति में सभी 33 प्रोबेशनर्स अधिकारियों से सामान्य परिचय प्राप्त किया गया। इसके उपरांत अधिकारियों को Soil & Water Conservation Measures and Watershed Management E&ercise विषय पर गूगल अर्थ एवं क्यूजीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोजेक्ट तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के पश्चात समस्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित समूहों के अनुसार चयनित नालों में जाकर स्थल निरीक्षण एवं ग्राउंड ट्रूथिंग की गई।

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से प्राप्त सूचना पर 04 बाल विवाह रोके गए, प्रशासन की त्वरित कार्यवाही

मुंगेली(समय दर्शन)। जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्यवाही कर बाल विवाह रोकने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजूला शर्मा तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी गोपाल लांझी के मार्गदर्शन में चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई और संबंधित पुलिस थाना की संयुक्त टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। हाल ही में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त चार अलग-अलग सूचनाओं के आधार पर जिले के विभिन्न गांवों में संभावित बाल विवाह को समय रहते रोकने में सफलता मिली है। सूचना मिलते ही संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और संबंधित परिवारों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाइश दी। अधिकारियों ने बताया कि कानून के अनुसार बालिका की न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 वर्ष तथा बालक की 21 वर्ष निर्धारित है।

भाजपा राज में अफीम की खेती से नशे का साम्राज्य खड़ा हो रहा– नवीन जायसवाल

कवर्धा (समय दर्शन)। धान का कटोरा कहे जाने वाले छग को जगह जगह अफीम की खेती से नशे का गढ़ बनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज उग्र प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय को घेरा।

जिला मुख्यालय कवर्धा स्थित कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेस की मासिक बैठक व भाजपा कार्यालय घेराव

हुआ, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में संगठनात्मक पूर्णता और पार्टी की मजबूती को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि जिला अंतर्गत सभी बूथ, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर संगठनात्मक ढांचा तत्काल प्रभाव से पूर्ण किया जाएगा।

बैठक में प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार और भाजपा सरकार के संरक्षण में सामने आ रही अफीम की खेती के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे के कारोबार को रोकने में भाजपा सरकार पूरी तरह विफल रही है, बल्कि अब तो भाजपा से जुड़े नेताओं के खेतों में ही अफीम की खेती उजागर हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे और भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी पदम कोठारी ने कहा कि भाजपा शासन में प्रदेश के चौक-चौराहों और दुकानों में अवैध शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री खुलेआम हो रही है। इससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है और समाज में गलत माहौल बन रहा है। एक तरफ भाजपा सरकार नशा मुक्त समाज बनाने का ढोंग करती है, वहीं दूसरी तरफ उनके ही नेता अपने खेतों में अफीम जैसी नशीली फसल उगाते पकड़े जा रहे हैं।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती आखिर किसके संरक्षण में हो रही थी। बिना राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर नशीले पदार्थों की खेती संभव नहीं हो सकती। जिस खेत में यह खेती पाई गई है, वह व्यक्ति भाजपा किसान मोर्चा का पूर्व पदाधिकारी रह चुका है और वर्तमान में भाजपा का सक्रिय नेता बताया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि नशे के इस काले कारोबार को कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है।

बोर एवं कुओं को सुरक्षित रूप से ढकने के दिए निर्देश

कलेक्टर-एसएसपी ने कानून-व्यवस्था के संबंध में ली बैठक

दुर्घटना के मामलों में पीएम राहत योजना के अंतर्गत पंजीयन करने दिए निर्देश

मुंगेली(समय दर्शन)। कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में जिले में कानून-व्यवस्था के संबंध में बैठक ली। बैठक में जिले की वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति, समन्वय तथा विभिन्न प्रकरणों के निराकरण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान पीएम राहत योजना से संबंधित वीडियो का अवलोकन किया गया तथा अधिकारियों को योजना और उससे जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में होने वाले सभी दुर्घटना (एक्सीडेंट) के मामलों का पीएम राहत योजना के अंतर्गत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि हिट एंड रन तथा पीएम राहत से संबंधित प्रकरणों में गंभीरता से कार्य करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने पर खाद्य एवं औषधि विभाग के सहायक संचालक तथा नगर पालिका मुंगेली के (सीएमओ) को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि सभी शासकीय एवं पात्र निजी अस्पतालों के बाहर पीएम राहत योजना से संबंधित पोस्टर एवं हेल्पलाइन नंबर चस्पा किए जाएं। साथ ही जिला अस्पताल में पीएम राहत योजना से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले में अफीम व अन्य मादक पदार्थों की अवैध खेती तथा पेड़ों की कटाई के संबंध में चर्चा कर कृषि, उद्यानिकी, राजस्व, खाद्य एवं औषधि विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर जांच करने और अवैध खेती पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही वनांचल क्षेत्रों में वन विभाग की टीम द्वारा भी नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गैस, पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति में कमी के कारण यदि कहीं कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है, तो वहां राजस्व एवं पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। साथ ही संबंधित एजेंसियों में उपलब्ध स्टॉक की जानकारी राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से ली जाएगी, ताकि जिले में आमजन के बीच किसी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति उत्पन्न न हो।

कलेक्टर ने खाद्य एवं औषधि विभाग के सहायक संचालक को निर्देशित किया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स की नियमित रूप से जांच की जाए तथा नारकोटिक्स श्रेणी की दवाइयों के अवैध विक्रय पर कड़ी निगरानी रखते हुए रोकथाम की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आबकारी विभाग से पूछा कि निर्धारित राजस्व प्राप्त करने में विभाग को क्या समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने आबकारी एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि अवैध रूप से शराब बेचने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कमी न हो। साथ ही जिले में कहीं भी कच्ची शराब बनाए जाने पर आबकारी, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में स्थित बोर एवं कुओं की जानकारी एकत्रित कर उन्हें सुरक्षित रूप से कवर कराया जाए, ताकि किसी भी आमजन के जान-माल को खतरा न हो। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देशित किया कि वे संयुक्त रूप से समन्वय बनाकर पीएम राहत एवं हिट एंड रन के मामलों का बेहतर ढंग से निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा गया कि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न ले सके। एसएसपी ने कहा कि गैस, पेट्रोल एवं डीजल की कमी जैसे संवेदनशील मामलों में यदि कहीं कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है, तो पुलिस की टीम उसे पूरी समझदारी और सतर्कता के साथ संभालेगी।

जिला जेल जांजगीर में बंदियों की स्वास्थ्य जांच और हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण शिविर आयोजित

जांजगीर-चांपा (समय दर्शन)। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला जेल परिसर जांजगीर में बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनीता श्रीवास्तव ने बताया कि इस दौरान आधुनिक हैंड हेल्ड एक्स-रे मशीन के माध्यम से टीबी की स्क्रीनिंग की गई तथा बंदियों को हेपेटाइटिस-बी संक्रमण से बचाव हेतु टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण के माध्यम से बचाव एवं जागरूकता सुनिश्चित करना था।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में हैंड हेल्ड डिजिटल एक्स-रे मशीन के माध्यम से टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में उच्च जोखिम समूह के अंतर्गत जिला जेल परिसर जांजगीर में बंदियों की स्वास्थ्य जांच की गई। 09 मार्च 2026 से प्रारंभ इस अभियान के तहत पहले दिन 63 बंदियों तथा 10 मार्च 2026 को 106 बंदियों की स्क्रीनिंग की गई। इस प्रकार कुल 169 बंदियों की जांच की गई, जिनमें से 28 बंदियों का चेस्ट एक्स-रे कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में जिला नोडल अधिकारी (एनटीईपी) डॉ. पुष्पेंद्र लहरे, प्रोग्राम कंसल्टेंट एवं जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. अंजुलता साहू, जिला नोडल अधिकारी डॉ. दीपक साहू, जेलर श्री डी.डी. टोण्डे, श्री विशाल पटेल, टीबी समन्वयक श्री उमाशंकर साहू, रेडियोग्राफर श्री जयेश साहू तथा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक श्री मुकेश कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रचार प्रसार दो दिवसीय कार्यशाला पाटन कालेज में 13 मार्च से

पाटन (समय दर्शन)। शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन में प्राचार्य डॉ नंदा गुरवारा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रचार प्रसार दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 13 एवं 14 मार्च 2026 को किया जा रहा है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन , आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग , अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मैथिलीशरण गुप्ता, संचालक रूसा , डॉ संजय तिवारी, कुलपति , हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, डॉ अनुपमा अस्थाना, क्षेत्रीय अपर संचालक दुर्ग संभाग होंगे । विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर तपेशचंद्र गुप्ता, क्षेत्रीय अपर संचालक,उच्च शिक्षा रायपुर संभाग व्याख्यान के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जानकारी प्रदान करेंगे । प्राचार्य डॉ नंदा गुरवारा ने जानकारी देते हुए बताया कि ह्रश्वक्क के प्रचार प्रसार हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 13 एवं 14 मार्च 2026 को किया जा रहा है जिसके अंतर्गत गीत , प्रह्सन , नृत्य-नाटिका, नुक्कड़ - नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न बिंदुओं की जानकारी प्रदान की जाएगी । इस आयोजन में दुर्ग संभाग के सभी महाविद्यालय से एक प्राध्यापक /सहा.प्रध्यापक एवं दो विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने हेतु पाटन महाविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया है और भोजन की व्यवस्था प्रतिभागियों को इस महाविद्यालय द्वारा दी गई है प्रतिभागियों को महाविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। दो दिवसी ह्रश्वक्क प्रचार प्रसार कार्यशाला के संरक्षक डॉ नंदा गुरवारा प्राचार्य , संयोजक श्री जागृत कुमार, रूसा प्रभारी, (सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र) डॉ गौरव शर्मा , ह्रश्वक्क संयोजक (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग) एवं सह् सन्योजक श्री बी एम साहू ,सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र तथा श्रीमती आराधना दुबे (सहायक प्राध्यापक वाणिज्य) हैं ।

कलेक्टर महोबे ने अकलतरा विकासखंड के ग्रामों में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण

स्वसहायता समूहों से की चर्चा,आजीविका गतिविधियों की सराहना

जांजगीर-चांपा (समय दर्शन)। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज जिले के विकासखंड अकलतरा अंतर्गत ग्राम तिलई, मुरलीकंजी ,मधुवा तथा कटघरी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न निर्माणाधीन एवं संचालित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री गोकुल रावटे सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम तिलई एवं मुरलीकंजी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। उन्होंने हितग्राहियों से चर्चा कर योजना के तहत मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। साथ ही कलेक्टर ने तिलई निर्माणाधीन पीडीएस भवन का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उपयोग की जा रही सामग्री तथा कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और इसे समय पर पूर्ण किया जाए, ताकि ग्रामीणों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधाएं सुचारू रूप से मिल सकें।

कलेक्टर ने ग्राम मुरलीकंजी एवं मधुवा में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्माण किए जा रहे चेक डेम का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि चेक डेम के निर्माण से क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने तथा शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने ग्राम कटघरी में जल संचय जनभागीदारी अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जनभागीदारी से सोक पिट निर्माण का कार्य का अवलोकन किया । उन्होंने ग्रामीणों को रिचार्ज पिट, सोखता गड्ढा तथा रेनवॉटर हार्वेस्टिंग जैसी जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रेरित किया।उन्होंने निर्देश दिए कि जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे गांवों में जल प्रबंधन की स्थिति बेहतर हो सके और भविष्य में जल संकट की स्थिति से बचाव किया जा सके।साथ ही ऐसे कार्यों से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत कटघरी में किए जा रहे निर्माण कार्यों को क्यूआर कोड स्कैन कर देखा जा सकता है, जिससे कार्यों की मॉनिटरिंग और निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी।कलेक्टर ने ग्राम कटघरी स्थित पीडीएस दुकान का निरीक्षण कर राशन वितरण की व्यवस्था का जायजा लिया।

उन्होंने प्रतिमाह ग्राम में चावल उत्सव आयोजित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री महोबे ग्राम कटघरी भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वसहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली।

धान खरीदी से लेकर भंडारण व्यवस्था तक, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में उठाए किसानों से जुड़े अहम सवाल

लोकसभा में गूँजी किसानों की आवाज़: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से माँगा फसलों की खरीद और भंडारण का पूरा हिसाब

नई दिल्ली/रायपुर :- सांसद एवं भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष श्री बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ सहित देशभर के किसानों के हितों को लेकर प्रखरता से आवाज़ उठाई है। श्री अग्रवाल ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा विभिन्न राज्यों से की जाने वाली फसलों की खरीद, विगत वर्षों में खरीदी गई फसलों की मात्रा और खर्च, अनाज परिवहन व्यवस्था, गोदामों की क्षमता तथा छत्तीसगढ़ के लिए खाद्यान्न आवंटन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया कि किसानों से होने वाली फसलों की खरीद व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अनाज के भंडारण और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने, रेलवे के माध्यम से बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था विकसित करने तथा राज्यों में गोदामों की क्षमता बढ़ाने जैसे विषयों पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

सांसद अग्रवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने जानकारी दी कि 1 फरवरी 2026 तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास 470.67 लाख टन की विशाल भंडारण क्षमता उपलब्ध है। इसमें 147.20 लाख टन क्षमता एफसीआई की अपनी है, जबकि 323.47 लाख टन क्षमता किराए पर ली गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य एजेंसियों के पास भी 381.92 लाख टन

की क्षमता सुरक्षित है। वहीं छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वर्ष 2025-26 (जनवरी 2026 तक) हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कुल 1153.380 हजार टन चावल आवंटित किया गया है। श्री अग्रवाल ने पिछले पाँच वर्षों में छत्तीसगढ़ से हुई धान की रिकॉर्ड खरीद और उस पर खर्च की गई करोड़ों की राशि का ब्यौरा भी सदन के पटल पर रखवाया। छत्तीसगढ़ में FCI और राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान का मूल्य वर्ष 2020-21 के ?13,419.90 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 27,009.44 करोड़ के आश्चर्यजनक आंकड़े तक पहुँच गया है। यह आधे दशक में मूल्य में लगभग 102त्न की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान खरीद की मात्रा 71.08 LMT से बढ़कर 116.42 LMT हो गई है। उल्लेखनीय है कि जहाँ FCI राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी सहित विभिन्न फसलों की खरीद करता है, वहीं छत्तीसगढ़ में धान मुख्य फोकस वाली फसल बनी हुई है, जो राज्य की संपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। श्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, राष्ट्रीय खाद्य भंडार में छत्तीसगढ़ का योगदान न केवल गर्व का विषय है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का एक स्तंभ भी है। अपने किसानों के लिए खरीद मूल्य को दोगुना करके और IT-समर्थित अनुकूलन मॉडल लागू करके, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी में उपजा हर दाना कुशलतापूर्वक अपने उद्देश्य को पूरा करे। हमारा ध्यान लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने और राज्य समिति के सदस्यों द्वारा गोदामों के नियमित ऑन-साइट निरीक्षण के माध्यम से भंडारित गुणवत्ता में सुधार करने पर है।

सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से खाद्यान्नों की सुरक्षित आवाजाही और गोदामों की कमी पर भी सवाल पूछे। जिसके जवाब में सरकार ने बताया कि खाद्यान्नों के सुचारू संचलन के लिए रेल मार्ग का 80% से अधिक उपयोग किया जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

टीवीएस ऑर्बिटर वी1 लॉन्च; अब BaaS मॉडल के साथ 49,999 से उपलब्ध

लखनऊ : दो और तीन पहिया वाहनों के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी टीवीएस मोटर कंपनी (टीवीएसएम) ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो को मजबूत करते हुए 1.8 kWh बैटरी के साथ टीवीएस ऑर्बिटर वी1 लॉन्च किया है। यह कंपनी की लाइन-अप में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने पूरे ईवी पोर्टफोलियो में बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल भी पेश किया है, जो ग्राहकों को अधिक लचीला ओनरशिप विकल्प देता है।

टीवीएस ऑर्बिटर वी1 और BaaS मॉडल के साथ कंपनी की ईवी स्कूटर रेंज अब 49,999 (एक्स-शोरूम दिल्ली, पीएम ई-ड्राइव सहित) से शुरू होती है। BaaS मॉडल से स्कूटर की शुरुआती कीमत कम हो जाती है और ग्राहकों को बैटरी की दीर्घकालिक सुरक्षा मिलती है। वहीं, जो ग्राहक बिना झंझट के ऑर्बिटर वी1 खरीदना चाहते हैं, वे इसे ?84,500 (एक्स-शोरूम दिल्ली, पीएम ई-ड्राइव सहित) में खरीद सकते हैं।

टीवीएस ऑर्बिटर वी1: नए भारत की स्मार्ट, सस्टेनेबल, अर्बन ईवी सवारी - 1.8 kWh बैटरी से लैस टीवीएस ऑर्बिटर वी1 को रोजमर्रा की शहरी यात्रा को आसान और व्यावहारिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ऑर्बिटर रेंज दो वेरिएंट में उपलब्ध है—वी1 (1.8 kWh) और वी2 (3.1 kWh)।

यह स्कूटर 86 किमी की प्रमाणित IDC रेंज देता है और लगभग 2 घंटे 20 मिनट में 0-80% चार्ज हो सकता है। इसमें कनेक्टेड मोबाइल ऐप, फ्रंट एलईडी हेडलैंप के साथ वाइज़र और इनकमिंग कॉल डिस्प्ले वाला कलर्ड एलसीडी क्लस्टर जैसे फीचर दिए गए हैं।

डिजाइन फिलॉस्फी- टीवीएस ऑर्बिटर वी1 का डिजाइन आधुनिक और व्यावहारिक है। इसमें 845 मिमी लंबी फ्लैट सीट, 290 मिमी का सीधा फुटबोर्ड, और चौड़ा व ऊंचा हैंडलबार दिया गया है, जो आरामदायक राइडिंग पोजिशन देता है। साथ ही इसमें 34 लीटर अंडर-सीट स्टोरेज है, जिसमें दो हेलमेट तक रखे जा सकते हैं।

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ और गैलेक्सी बड्स4 सीरीज़ भारत में उपलब्ध

नई दिल्ली: सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी नई गैलेक्सी S26 सीरीज़ और गैलेक्सी बड्स4 सीरीज़ की वैश्विक उपलब्धता की घोषणा कर दी है। सैमसंग की तीसरी पीढ़ी के एआई स्मार्टफोन्स के रूप में गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, गैलेक्सी S26+ और गैलेक्सी S26 उपयोगकर्ताओं को अधिक सहज और स्मार्ट एआई अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे वे कम चरणों में अधिक काम कर सकते हैं। गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के बाद से नई सीरीज़ को दुनियाभर में शानदार प्रतिक्रिया मिली है। शुरुआती प्री-ऑर्डर आंकड़ों में दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें गैलेक्सी S26 अल्ट्रा सबसे लोकप्रिय मॉडल बनकर उभरा है, जिसे वैश्विक स्तर पर 70 प्रतिशत से अधिक ग्राहकों ने चुना। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा: उन्नत तकनीक का नया अनुभव- गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में सैमसंग की कई उन्नत तकनीकों को एक साथ शामिल किया गया है। इसमें शक्तिशाली प्रदर्शन, इंडस्ट्री-लीडिंग कैमरा सिस्टम, बेहतर गैलेक्सी एआई अनुभव और दुनिया का पहला बिल्ट-इन प्राइवेसी डिस्प्ले दिया गया है। यह प्राइवेसी डिस्प्ले डिस्प्ले तकनीक में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो पिक्सल स्तर पर उपयोगकर्ता की गोपनीयता की सुरक्षा करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन इस तरह तैयार किया गया है कि रोजमर्रा के उपयोग में स्क्रीन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना प्राइवेसी सुरक्षित रहे।

पोको इंडिया ने लॉन्च किया पोको C85x 5G: यूजर्स को मिलेगा दमदार परफॉर्मेंस, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और शानदार डिस्प्ले

पोको इंडिया ने आज पोको C85x5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा की। यह स्मार्टफोन रोज़मर्रा के यूजर्स के लिए भरोसेमंद परफॉर्मेंस, बड़ा शानदार डिस्प्ले और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी लाइफ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। छात्रों, पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वालों और रोज़ाना भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहने वाले यूज़र्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया यह डिवाइस कुशल हार्डवेयर, व्यावहारिक फीचर्स और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आता है।

रोज़मर्रा के उपयोग के लिए भरोसेमंद परफॉर्मेंस- पोको C85x5G में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm तकनीक पर बना है और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ बैटरी की बचत भी करता है। इसमें 2.2GH5 तक की स्पीड वाले A78 परफॉर्मेंस कोर और Mali-G57 GPU है, जिससे ब्राउज़िंग, सोशल मीडिया, वीडियो देखना और हल्की-फुल्की गेमिंग आसानी से हो जाती है। यह स्मार्टफोन 4GB + 64GB और 4GB + 128GB वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज दिया गया है। इससे ऐप्स तेज़ी से लोड होते हैं और मल्टीटास्किंग भी आसानी से होती है। यूज़र्स स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा भी सकते हैं, जिससे फोटो, वीडियो, ऐप्स और फाइलों के लिए पर्याप्त जगह मिलती है।

प्रथम पृष्ठ का शेष

4 साल बीते, टेंडर के बाद भी झीरम व कांदानार के बीच नहीं बनी सड़क

सदन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अनुपस्थिति में वन एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि नक्सलवाद के कारण जैसा सर्वे होना था नहीं हुआ। नाली समेत अन्य निर्माण कार्य नहीं हो पाए। वर्तमान स्थिति में कार्यों को डीएमएफ फंड से चिन्हांकित किया गया है। ठेकेदार को लगभग 4 करोड़ 23 लाख का भुगतान हुआ है। एक वर्ष के भीतर इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। किरण देव ने कहा कि 4 वर्ष पहले यह काम शुरु हुआ था। 4 बरसातें निकल गईं। काम टुकड़ों में हुआ। जब भी बरसात आती है मुरुम मिट्टी बह जाती है। यह जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर का मामला है, जहां सबसे ज्यादा सड़क की आवश्यकता है। अधिकारियों की टीम से लगातार इसकी समीक्षा कराएं। अन्यथा 4 साल और लग जाएगा। केदार कश्यप ने कहा कि आपका प्रश्न वाजिब है और सरकार की भी यही मंशा है। यह घोर नक्सल प्रभावित पहाड़ी वाला वन क्षेत्र रहा है। घाट कटिंग का काम बेहद चुनौतीपूर्ण है। शेष काम के लिए 5 करोड़ 59 हजार 69 हजार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और टेंडर भी कर दिया गया है। किरण देव ने कहा कि चिंता इस बात की है ढाई साल में मामला वहीं का वहीं है। 2 माह बाद फिर बरसात आ जाएगी और पहले की तरह मुरुम और मिट्टी बह जाएगी। केदार कश्यप ने कहा कि आश्वस्त करता हूं कि 20 दिनों के भीतर अधिकारी स्थल का अवलोकन करेंगे। जो भी एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी लिया जाएगा।

डीएसआर से पानी की खपत में 35 प्रतिशत तक कमी और खेती की लागत में 14,000 प्रति हेक्टेयर तक बचत संभव; एफएसआईआई ने इसे व्यापक रूप से अपनाने का आह्वान किया

नई दिल्ली: भारत में जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव, श्रम लागत में वृद्धि और कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की आवश्यकता के बीच, फेडरेशन ऑफसीड इंडस्ट्री ऑफइंडिया (FSII) ने मंगलवार को डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) पर आयोजित एक सम्मेलन में अधिक संसाधन-कुशल खेती पद्धतियों की ओर बढ़ने का आह्वान किया। विशेषज्ञों ने कहा कि ष्डस्क्र एक जलवायु-अनुकूल और संसाधन-कुशल विकल्प के रूप में उभर रहा है, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय में सुधार करने की क्षमता रखता है।

FSII ने ÷सस्टेनेबल और लाभकारी धान उत्पादन के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस (ष्डस्क्र)÷ विषय पर अपने सम्मेलन का दूसरा संस्करण 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली के ह्लस्ट्र कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया। इस सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। चर्चा का उद्देश्य भारत के धान उत्पादक क्षेत्रों में ष्डस्क्र को व्यापक स्तर पर अपनाने के अवसरों और चुनौतियों पर विचार करना और इसके प्रसार को तेज करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करना था।

भारत में धान की खेती पर अत्यधिक भूजल दोहन, विशेषकर उत्तर-पश्चिमी धान क्षेत्र में, बढ़ता दबाव डाल रहा है- फेडरेशन ऑफसीड इंडस्ट्री ऑफइंडिया (FSII) के अध्यक्ष और सवाना सीड्स के सीईओ एवं एमडी अजय राणा ने कहा, ÷पंजाब में भूजल दोहन वार्षिक पुनर्भरण का लगभग 156त्न तक पहुँच चुका है।

रायपुर में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने कांग्रेस की कवायद, अरुण वोरा ने ली पार्षदों व छाया पार्षदों की बैठक

रायपुर :- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा रायपुर शहर के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए पूर्व विधायक अरुण वोरा ने आज कांग्रेस भवन गांधी मैदान में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पार्षदों एवं छाया पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में अरुण वोरा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि रायपुर शहर के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक वार्ड के सभी मतदान केंद्रों में जल्द से जल्द बूथ कमेटियों का गठन किया जाना है। उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम बनाना बेहद आवश्यक है। बूथ कमेटियों के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा और जनहित के मुद्दों को सीधे जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने पार्षदों एवं छाया पार्षदों को निर्देशित किया कि अपने अपने वार्डों में बूथ कमेटियों का गठन

प्राथमिकता के साथ करें तथा प्रत्येक बूथ में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए। साथ ही बीएलए 2 की नियुक्ति भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि मतदान केंद्र स्तर पर संगठन की मजबूती सुनिश्चित हो सके। बैठक में यह भी तय किया गया कि संगठन की नीतियों एवं वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन के अनुरूप सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। सभी वार्डों में बूथ कमेटियों के गठन की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर उसकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी। इस दौरान शहर अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन पंकज शर्मा प्रमोद दुबे कुलदीप जुनेजा ऐजाज ढेबर आकाश तिवारी सुंदर जोगी मनीराम साहू देवेंद्र यादव सतनाम पनाग जी श्रीनिवास प्रकाश जगत सतनारायण नायक जयंत साहू अमितेश भारद्वाज कामरान अंसारी उत्तम साहू बंशी कन्नौजे सहित पार्षद एवं छाया पार्षद उपस्थित थे।

कस्टमर डे 2026: एयरटेल ने ग्राहकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी संस्कृति को और मजबूत किया

ग्राहकों को मिलने वाले अनुभव को और बेहतर बनाने और बड़े स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान करने पर नए सिरे से ध्यान

नई दिल्ली: एयरटेल ने आज 'कस्टमर डे 2026' मनाया। यह संगठन के भीतर चलाया गया एक व्यापक अभियान है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों की समस्याओं को समझना और उनके अनुभव को लगातार बेहतर बनाना है। इस पहल के तहत एयरटेल के लगभग बीस हजार कर्मचारियों ने अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर सीधे फील्ड में काम किया। इनमें नेतृत्व करने वाली टीम के सदस्यों से लेकर विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शामिल थे। इन कर्मचारियों ने फ्रंटलाइन टीमों के साथ मिलकर काम किया, फील्ड इंजीनियरों के साथ जाकर उनके काम को करीब से देखा, घरों और दुकानों का दौरा किया और रिटेल व सर्विस सेंटरों पर ग्राहकों से बातचीत की। इसका उद्देश्य ग्राहकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को बिना किसी फिल्टर के समझना है। एयरटेल में कस्टमर डे संगठन के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर भी है जब वह ठहरकर आत्ममंथन करता है और खुद से एक सीधा लेकिन अहम सवाल पूछता है कि हम अपने ग्राहकों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं।

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए एयरटेल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शाश्वत शर्मा ने कहा, कस्टमर डे हमें हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि हम ग्राहकों की बात पूरे ध्यान से सुनें, खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए चुनौती दें और तत्परता के साथ कार्रवाई करें। इससे ग्राहकों को होने वाली समस्याओं को हल करने, सेवाओं को सरल बनाने और हर दिन लाखों ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा के स्तर को लगातार बेहतर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होती है। ग्राहकों की समस्याओं को हल करने की यह परंपरा और संस्कृति ही एयरटेल के 'कस्टमर फर्स्ट' (ग्राहक प्रथम) के विचार से जुड़े कई नवाचारों का केंद्र रही है। स्पैम और धोखाधड़ी से सुरक्षा को मजबूत करने से लेकर, एयरटेल ऐप के माध्यम से डिजिटल प्रक्रियाओं को सरल और सहज बनाने और एआई सक्षम उपकरणों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने जैसे एयरटेल के समाधान ग्राहकों की बातों को सुनकर और उनकी वास्तविक जरूरतों को समझकर ही तैयार किए गए हैं। कस्टमर डे एयरटेल के इस विश्वास को भी पुख्ता करता है कि ग्राहकों के अनुभव में सुधार कोई कभी-कभार होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्राहकों की बातों को ध्यान से सुनकर और उनके सुझावों के आधार पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए कंपनी प्रक्रियाओं को सरल बना रही है, अनावश्यक जटिलताओं को दूर कर रही है और ऐसी सेवाएं तैयार कर रही है जो विश्वसनीय, सहज और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली हों। यह अभियान पूरी एयरटेल टीम को एक साझा और स्थायी उद्देश्य के लिए एकजुट करता है।

LEVI'S® के BEHIND EVERY ORIGINAL अभियान की आलिया भट्ट के साथ नई शुरुआत

मुंबई— Levi's® ब्रांड अपने 2026 के वैश्विक अभियान Behind Every Original को भारत में लेकर आया है, जिसमें ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में नज़र आ रही हैं। पिछले 150 से अधिक वर्षों से, रू1द्व'ह्य0 उन लोगों की पहली पसंद रहा है जो संस्कृति को नई दिशा देते रहे हैं। संगीत और खेल से लेकर फैशन और कला तक, Levi's® जींस हर उस महत्वपूर्ण मोड़ की गवाह रही है जहाँ बदलाव की शुरुआत हुई। इसे वे लोग पहनते हैं जो न केवल प्रगति की राह पर चलते हैं, बल्कि आने वाले कल की दिशा भी तय करते हैं। Behind Every Original अभियान इसी महान विरासत को आगे बढ़ाता है। यह वैश्विक स्तर पर मौलिकता के पीछे की गहरी सोच का जश्न मनाता है—वह जिज्ञासा, अटूट विश्वास और दुनिया को एक अलग नज़रिये से देखने का साहस, जो असल प्रगति को जन्म देते हैं। इस अभियान का मुख्य केंद्र अभिनेत्री आलिया भट्ट हैं, जो एक ऐसी कलाकार और वैश्विक सांस्कृतिक आइकन हैं जिनकी यात्रा निरंतर विकास, आत्मविश्वास और अद्वितीय व्यक्तित्व का मेल है। उनका यह सफर आज की उस पीढ़ी की आवाज़ है जो बनावटी पूर्णता (Perfection) के बजाय असलियत और प्रामाणिकता को चुनती है, और यही खूबी उन्हें की इस वैश्विक कहानी का एक सच्चा प्रतिनिधि बनाती है।

थाना उरला एवं चौकी रामनगर में की गई नारकोटिक एक्ट के तहत कार्यवाही

अलग-अलग प्रकरणों में कुल 08 किलो 321 ग्राम गांजा के साथ 2 गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से कुल 08 किलो 321 ग्राम गांजा किया गया है जप्त।

जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 4,16,050/- रूपये।

चौकी रामनगर में हिरासत में लिया गया आरोपी अनिल अहीरवार है मूलत: विदिशा मध्यप्रदेश का निवासी।

प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में की जा रहीं है विस्तृत पूछताछ।

रायपुर। आरोपियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 86/26 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट तथा थाना गुढ़ियारी में नारकोटिक एक्ट के तहत क्रमश: अपराध किया गया है पंजीबद्ध।

विवरण - पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर के दिशा-निर्देश में नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु मादक पदार्थो की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से उनकी खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में नॉर्थ जोन के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

इसी तारतम्य में दिनांक 10.03.2026 को थाना उरला पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बाजार चौक के पास 01 व्यक्ति अपने पास मादक पदार्थ गांजा रखा है तथा बिक्री की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री आकाश मरकाम तथा सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णिमा लामा द्वारा थाना प्रभारी उरला को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को गांजा के साथ रंगेहाथ पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया। जिसपर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान में जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पतासाजी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम सुमीत वर्मा निवासी उरला रायपुर का होना बताया गया, टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी सुमित वर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 किलो 115 ग्राम गांजा जप्त किया गया है।

इसके साथ ही थाना गुढ़ियारी चौकी रामनगर क्षेत्र से भी आरोपी अनिल अहीरवार को 05 किलो 206 ग्राम गांजा के साथ पकड़कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जिस पर दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 08 किलो 321 ग्राम गांजा जुमला कीमती लगभग 4,16,050/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 86/2026 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट तथा थाना गुढ़ियारी में भी नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी -

01. सुमित वर्मा पिता राधेश्याम वर्मा उम्र 19 साल निवासी साई नगर पानी टंकी के पास थाना उरला रायपुर।

02. अनिल अहीरवार पिता राम किशन उम्र 32 साल निवासी अहमदपुर बाडेर थाना विदिशा मध्यप्रदेश।

संपादकीय

समाधान ढूंढना सही दृष्टिकोण

क्या अब ये बात भरोसे के साथ कही जा सकती है कि न्यायपालिका ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर ली है? आखिर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की धारणा इस हद तक क्यों पहुंच गई कि पाठ्य-पुस्तक में उसका जिक्र होने लगा? एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की किताब में न्यायपालिका के सामने मौजूद चुनौतियों के जिक्र से बार एसोसिएशन के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश भी आहत हुए। पुस्तक में जिन चुनौतियों का उल्लेख है, उनमें विचाराधीन मुकदमों की विशाल संख्या, न्यायाधीशों की कमी, और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। न्यायपालिका में इससे इतनी नाराजगी फैली कि प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया। कहा कि कि संस्था के प्रमुख के बतौर उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। उधर बार एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि किताब में संसद में आपराधिक छवि के व्यक्तियों की मौजूदगी और शासन के दूसरे क्षेत्रों में मौजूद भ्रष्टाचार की चर्चा एनसीईआरटी ने क्यों नहीं की? चूंकि न्यायपालिका के पास अवमानना कार्यवाही की ताकत है, इसलिए प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणियों का तुरंत असर हुआ। एनसीईआरटी ने संबंधित किताब पर अफसोस जताते हुए उसकी बिक्री तुरंत रोक दी और उस हिस्से को हटाने का एलान किया, जिस पर विवाद खड़ा हुआ। मगर क्या न्यायपालिका से जुड़े लोग ये बात भरोसे के साथ कह सकने की स्थिति में हैं कि अब उन्होंने अपनी संस्था की प्रतिष्ठा की रक्षा कर ली है? क्या उनके लिए यह प्रश्न उठाना बेहतर नहीं होता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की धारणा इस हद तक क्यों पहुंच गई कि पाठ्य-पुस्तक में उसका जिक्र होने लगा? क्या यह अधिक उचित एवं सकारात्मक नजरिया नहीं होता कि वे ऐसी धारणा की जड़ तक पहुंचेंगे और उसका निवारण करेंगे? इस बात से कोई इनकार नहीं है कि बात सभी जगहों पर मौजूद खामियों की होनी चाहिए। मगर एक जगह खामी है, तो उससे दूसरे स्थलों पर मौजूद बुराइयों को सही बताने का तर्क तो नहीं मिल जाता? सार्वजनिक लाभ के नजरिए से कहा जाता है कि धूप सर्वश्रेष्ठ कीटाणु नाशक है- यानी पारदर्शिता भूल-सुधार का आरंभिक उपाय है। अत: संदेह, आरोप, या धारणाओं को दबाने की कोशिश के बजाय उनसे संबंधित तथ्यों को सामने लाना, उन पर बहस करना और जहां समस्या नजर आए उसका समाधान ढूंढना सही दृष्टिकोण माना जाएगा। और उससे ही विभिन्न संस्थाओं सहित पूरे राज्य-तंत्र की प्रतिष्ठा सुरक्षित हो सकेगी।

भारत में सिर्फ टेलर मेड एप्लीकेशन तैयार होंगे

हरिशंकर व्यास

दुनिया भर में एक के बाद एक बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। पहले जनवरी में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई। उसके बाद फरवरी में जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई। फिर दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ। अगले महीने भारत में रायसीना डायलॉग्स होंगे। सवाल है कि इन तमाम सम्मेलनों में भारत के लिए क्या है? क्या दुनिया भारत को पूछ रही है या भारत किसी भी मामले में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है? आर्थिक मंच की बैठक में या सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में या एआई समिट में भारत के पास दिखाने के लिए क्या था? ले देकर भारत के पास एकमात्र चीज यह है कि भारत दुनिया भर के उत्पाद खरीद सकता है। चाहे उपभोक्ता उत्पाद हों या हथियार हों या एआई की तकनीक हो, भारत एक खरीदार है। इसके अलावा कोई भारत की परवाह नहीं करता। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी दुनिया की प्राथमिकता दिखी। जिस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सेशन होना था उस समय पूरा हॉल भरा हुआ था, लोग खड़े होकर फ्रांस और यूक्रेन की बात सुन रहे थे। यूरोप के लोगों के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध एक चिंता की बात है। लेकिन इसके तुरंत बाद भारत और जर्मनी का सेशन था, जिसमें पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ था। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि भारत क्या कह रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत ने किसी तरह की भूमिका नहीं निभाई। भारत ने सिर्फ बयानबाजी की। प्रधानमंत्री मोदी ने हर जगह कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। उनको लगता था कि यह बहुत बड़ा वाक्य है और इसे बोलने से युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन युद्ध के चार साल हो गए। यूरोप के सारे देश यूक्रेन की मदद करते रहे लेकिन भारत इस दौरान रूस से तेल खरीदता रहा। तभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत अप्रासंगिक था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात कह आए लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उससे पहले दावोस में भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लेने पहुंचे थे। लेकिन पूरा सम्मेलन अमेरिका और यूरोप के मुद्दे पर केंद्रित रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मंत्रियों के साथ पहुंचे थे और अमेरिका ने अपना पैवेलियन बनवाया था। लेकिन दावोस में यूरोप के देशों ने कमाल की एकजुटता दिखाई। ट्रंप ने ग्रीनलैंड लेने की बता कही तो अगली कतार में बैठे ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति उठ कर चले गए। उनके साथ साथ यूरोप के ज्यादातर देशों के नेता वहां से निकल गए। सबने बाहर जाकर कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। यूरोप के देशों ने मिल कर ट्रंप की दादागिरी का मुकाबला किया और मजबूरी में ट्रंप को टैरिफ लगाने के फैसले से पीछे हटना पड़ा। लेकिन वहां भी भारत के नेता क्या कर रहे थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने दावोस जाकर अपने ही राज्य के एक बड़े बिल्डर लोढा समूह के साथ एग्रीमेंट किया। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में टाटा समूह के साथ करार किया। सोचें, भारत के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दावोस जाकर ऐसे ही घूमते रहे और अपनी देशी कंपनियों से ही निवेश का करार करके लौटे। ऐसे ही दिल्ली के एआई समिट में हुआ है। दुनिया भर की एआई कंपनियों ने भारत में अपने लिए बाजार की संभावना देखी और निवेश का वादा किया। यह कितनी हैरानी की बात है कि भारत ने ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक्स के डारियो अमोदाई, गूगल के सुंदर पिचाई आदि की बात की लेकिन किसी दूसरे देश ने भारत के सर्वम या परम की बात नहीं की।

जलियांवाला बाग से कैक्सटन हॉल तक शहीद-ए-आजम ऊधम सिंह की अमर गाथा

सुनील कुमार महला

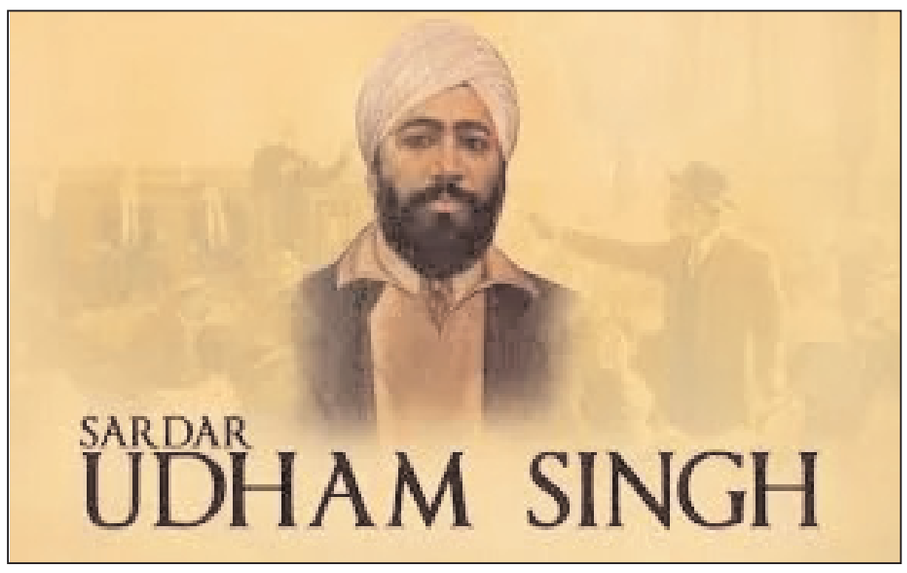

शहीद-ए-आजम सरदार उधम सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन दीपस्तंभों में से एक हैं, जिनका नाम साहस और अटूट संकल्प का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो उधम सिंह (राम मोहम्मद सिंह आज़ाद) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उनके बचपन का नाम शेर सिंह था तथा उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को सुनाम,जिला संगरूर,पंजाब में हुआ था।उनके पिता का नाम सरदार टहल सिंह था, जो रेलवे ओवरसियर (चौकीदार) के रूप में कार्य करते थे तथा ?उनकी माता का नाम नारायण कौर था।पाठकों को बताता चलूं कि बचपन में ही उनके माता-पिता का निधन हो गया था, कहते हैं कि उनका पालन-पोषण अमृतसर के एक अनाथालय में हुआ था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार माता-पिता के साये के बिना, उन्हें और उनके बड़े भाई (मुक्ता सिंह) को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी।यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अनाथालय में ही रहकर पूरी की और वहीं से 1918 में मैट्रिक की परीक्षा पास की।13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए भीषण जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने उधमसिंह के जीवन की दिशा बदल दी। दरअसल, उस समय वे अमृतसर में ही थे, और कहा जाता है कि वे घायल लोगों को पानी पिला रहे थे। इस क्रूर घटना ने उनके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने इस नरसंहार का बदला लेने का संकल्प लिया। वे इस घटना के लिए पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'ड्वायर को जिम्मेदार मानते थे।जलियांवाला बाग हत्याकांड पृष्ठभूमि:-दरअसल, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट अधिनियम-1919 (जिसे काला कानून भी कहा गया) पारित किया। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी।इस अन्यायपूर्ण कानून का पूरे देश में विरोध हुआ। इसी विरोध के दौरान अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी रिहाई की मांग और रॉलेट एक्ट(अधिनियम) के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई।वैशाखी का दिन और विशाल भीड़:-13 अप्रैल 1919 को वैशाखी का पर्व था। इसलिए लगभग 10,000 पुरुष, महिलाएँ और बच्चे जलियांवाला बाग में एकत्र हो गए थे। कई लोग

राजनीतिक सभा के लिए आए थे, जबकि अनेक लोग केवल मेले के कारण वहाँ पहुँचे थे। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि उस समय जलियांवाला बाग कोई व्यवस्थित बगीचा नहीं था, बल्कि यह मकानों से घिरा एक बड़ा खाली मैदान था तथा वहाँ आने-जाने के लिए केवल एक संकरा प्रवेश मार्ग था और चारों ओर ऊँची दीवारें व मकान स्थित थे।जब इस विशाल सभा की सूचना ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर को मिली, तो वह लगभग 90 सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। कहते हैं कि उसके साथ दो मशीनगनों से लैस बख्तरबंद गाड़ियाँ भी थीं, लेकिन बाग का रास्ता संकरा होने के कारण वे अंदर नहीं जा सकीं।गोलाबारी और भीषण नरसंहार:-जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी की और लगभग 1650 राउंड गोलियाँ चलाईं।गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक गोला-बारूद लगभग समाप्त नहीं हो गया। चूँकि, सैनिकों ने सभी रास्तों को घेर लिया था, इसलिए लोग वहाँ से भाग नहीं सके और सैकड़ों लोग वहीं गिर पड़े।अपनी जान बचाने के लिए कई लोग बाग में स्थित एक कुएँ में कूद गए। बाद में उस कुएँ से 100 से अधिक शव निकाले गए। आज यह स्थान 'शहीदी कुआँ' के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है।मृतकों की संख्या और अमानवीय दमन:-जलियांवाला बाग हत्याकांड में मृतकों की संख्या को लेकर विभिन्न आँकड़े मिलते हैं।ब्रिटिश सरकारी अभिलेखों के अनुसार 379 लोग मारे गए और लगभग 200 घायल हुए।अमृतसर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय की सूची में 484 शहीदों का उल्लेख मिलता है। वहीं पर जलियांवाला बाग की सूची में 388 शहीदों का उल्लेख है।भारतीय अनौपचारिक आँकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 2000 घायल हुए। ब्रिटिश अभिलेखों के अनुसार मृतकों में 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक छह सप्ताह का शिशु शामिल था। कहते हैं कि इस घटना के बाद पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और घायलों को अस्पताल ले जाने तक की अनुमति भी नहीं दी गई। परिणामस्वरूप, कई लोग रातभर तड़पते हुए दम तोड़ बैठे। नरसंहार के बाद अमृतसर में 'मार्शल लॉ' लागू कर दिया गया था और लोगों के आवागमन तथा संचार पर कड़ी पाबंदियाँ लगा दी गईं। वास्तव में, डायर ने शहर में कई कठोर आदेश लागू किए। इनमें सबसे कुख्यात था 'क्रॉलिंग ऑर्डर', जिसके तहत जिस गली में एक अंग्रेज महिला पर हमला हुआ था, वहाँ से गुजरने वाले भारतीयों को पेट के बल रेंगकर(क्रॉलिंग करते हुए) जाने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अतिरिक्त, कई स्थानों पर लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े भी लगाए गए।ऊधम सिंह का प्रतिशोध:-जलियांवाला बाग की इस घटना ने ऊधम सिंह के मन में प्रतिशोध की तीव्र भावना उत्पन्न कर दी। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे कई वर्षों तक अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। दरअसल,उधम सिंह ने लगभग 21 साल तक धैर्य और संकल्प के साथ प्रतीक्षा की और अंतत: अपने देशवासियों के लिए न्याय का प्रतीक बन गए। कहते हैं कि इस दौरान उन्होंने अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की यात्राएँ भी कीं और विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। सरल शब्दों में कहें तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वे विभिन्न देशों (जैसे अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप) की यात्रा करते हुए 1934 में लंदन पहुँचे और वहां उन्होंने 'राम मोहम्मद सिंह आजाद' नाम अपनाया, जो भारत की सांप्रदायिक एकता का प्रतीक था। सरदार उधमसिंह,भगतसिंह को वे अपना गुरू मानते थे। यहां पाठकों को बताता चलूं कि उधम सिंह, शहीद भगत सिंह से उम्र में बड़े थे, फिर भी वे उन्हें अपना 'गुरु' और मार्गदर्शक मानते थे।1927 में जब वे भगत सिंह के कहने पर वापस भारत आए, तो उनके पास भारी मात्रा में हथियार और प्रतिबंधित साहित्य मिला, जिसके कारण उन्हें 5 साल की जेल हुई।?उनकी जेब में हमेशा भगत सिंह की एक तस्वीर रहती थी। इसके अलावा, उधमसिंह का गदर पार्टी(अमेरिका में सदस्य बनें) से सक्रिय जुड़ाव रहा।?वे महान क्रांतिकारी अजीत सिंह (शहीद भगत सिंह के चाचा) से बेहद प्रभावित थे और उनसे विदेश में मिले भी थे। उन्होंने भारत की आजादी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने का काम किया।बहुत कम लोग जानते हैं कि लंदन में रहते हुए अपनी पहचान छिपाने और पैसे कमाने के लिए उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में 'एक्स्ट्रा' के तौर पर काम किया था।?उन्होंने 'एलिफैंट ब्वाय' (1937) और 'द फेर फीदर्स' (1939) जैसी फिल्मों में छोटे रोल भी किए थे।माइकल ओ'ड्वायर की हत्या:-अंतत: 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में आयोजित एक सभा में उधमसिंह एक मोटी किताब के भीतर पिस्तौल छिपाकर पहुँचे। सभा के दौरान उन्होंने माइकल ओ'ड्वायर पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी।इस प्रकार उन्होंने जलियांवाला बाग के शहीदों के प्रति लिया गया अपना संकल्प पूरा किया। हालांकि, इसके तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।एक दिलचस्प तथ्य यह है कि ?कैक्सटन हॉल की घटना के बाद, उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी, क्योंकि वे चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चले कि भारतीय अपने अपमान और नरसंहार का बदला लेना जानते हैं।मुकदमा और फाँसी:-अदालत में उधमसिंह ने निर्भीक होकर कहा कि उन्होंने यह कार्य अपने देशवासियों पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए किया है। उनका प्रसिद्ध कथन था-' मैंने यह इसलिए किया, क्योंकि वह इसके योग्य था। वह मेरे लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया।' मुकदमे के बाद 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविले जेल में उन्हें फाँसी दे दी गई। यहां पाठकों को बताता चलूं कि लंदन की पेंटनविले जेल में कैद के दौरान, उधम सिंह ने 42 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जबरन खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन उनके हौसले को नहीं तोड़ सके। वे अंत तक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। बाद में 1974 में उनकी अस्थियाँ भारत लाई गईं और उन्हें देश के महान शहीदों में सम्मानित स्थान दिया गया। गौरतलब है कि उनके अवशेषों(अस्थियाँ) के कुछ हिस्से अमृतसर के जलियांवाला बाग में भी रखे गए हैं।अंत में निष्कर्षत: यही कहूंगा कि, ऊधम सिंह का जीवन अदम्य साहस, देशभक्ति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का महान उदाहरण है। जलियांवाला बाग जैसी भीषण घटना ने उनके मन में स्वतंत्रता और न्याय के लिए प्रबल संकल्प उत्पन्न किया, जिसे उन्होंने वर्षों बाद पूरा किया। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध की अमर गाथा बन गया। आज भी ऊधम सिंह का नाम देशभक्ति, त्याग और शहीदों के सम्मान के प्रतीक के रूप में श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। ऐसे महान क्रांतिकारी के जज्बे और उनकी शहादत को शत-शत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि।

एआई क्रांति की फसल काटने का बंदोबस्त

अजीत द्विवेदी

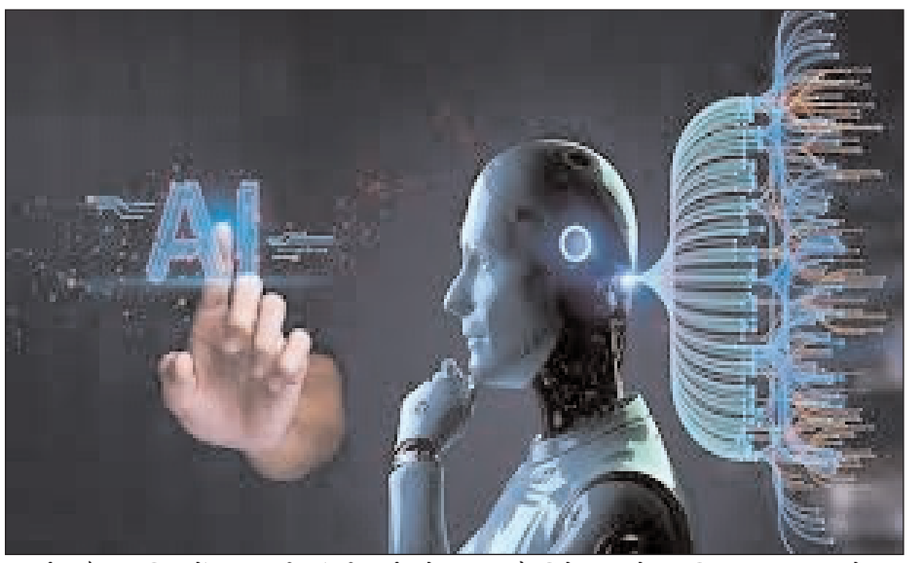

दिल्ली में हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत में एआई क्रांति की मजबूत आधारशिला रखने वाले कार्यक्रम साबित होगा या वक्ती मीडिया हाइप के बाद इसका भी मामला नेपथ्य में चला जाएगा और सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, जैसा पहले चलता रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अब तक हुई तमाम औद्योगिक और संचार क्रांतियों में भारत की भूमिका नगण्य रही है। पहली औद्योगिक क्रांति में भी भारत ने न कुछ आविष्कार किया और न कोई निर्माण किया।

उसी तरह संचार क्रांति में भी भारत का योगदान एक यूजर देश के रूप में ही रहा। भारत ने हर क्रांति में बने उत्पादों का इस्तेमाल किया। अगर सोशल मीडिया क्रांति में भारत की उपलब्धि यह है कि भारत में सबसे ज्यादा 45 करोड़ फेसबुक यूजर हैं तो एआई क्रांति में अभी तक भारत की उपलब्धि का आंकड़ा यह है कि भारत में चैटजीपीटी के अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा यूजर हैं। भारत में इनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या साढ़े 14 करोड़ है।

अब दुनिया भर की एआई कंपनियों में होड़ मची है कि किसके यूजर सबसे ज्यादा होंगे। गूगल को अपने जेमिनी के यूजर बढ़ाने हैं तो सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ मीटिंग के बाद मीडिया के सामने कहा कि उनकी कंपनी भारत के दो करोड़ कर्मचारियों को एआई के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देगा। इसी तरह सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपनएआई भी चैटजीपीटी के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण देगी। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 30 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। 30 साल पहले इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के ट्रेनिंग कैंप लगते थे। उनके पेशेवर भारत के लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल की जानकारी देते थे। लोगों को ईमेल और सर्च इंजन के इस्तेमाल में प्रशिक्षित किया जाता था।

आज भी वही इतिहास दोहरा रहा है। आप कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोलिए वहां सबसे ज्यादा विज्ञापन इस बात का आ रहा है कि एआई का इस्तेमाल करना सीखें और कमाई बढ़ाए। याद करें कैसे पहली संचार क्रांति के समय गली गली में कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर की दुकानें खुलीं, उसके बाद मोबाइल हैंडसेट के रिपेयर और सिम बेचने की दुकानें खुलीं और अब हर जगह एआई सिखाने की दुकानें खुल रही हैं।

सवाल है कि इसमें भारत का अपना क्या है? इसी एआई इम्पैक्ट समिट में भारत की कंपनी सर्वम ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। बेंगलुरू स्थित कंपनी ने पहला मल्टी बिलियन पैरामीटर का एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किया। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। आम लोगों के बीच यह नहीं पहुंचा है और न इसके पेशेवरों द्वारा लोगों को सर्वम के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी ओर अमेरिका की कंपनियों के प्लेटफॉर्म करोड़ों की संख्या में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चैटजीपीटी के कई वर्जन आ गए। उसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इसी तरह जेमिनी, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म का करोडों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के डीपसीक की बात छोड़ दें तो अमेरिकी कंपनियां पूरी दुनिया पर छा गई हैं। उनके यहां इस पर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है, जिसकी भारत में कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

अमेरिका अगले साल एआई पर साढ़े छह सौ बिलियन डॉलर यानी करीब छह लाख करोड़ रुपए का है। चीन अगले साल सौ बिलियन डॉलर यानी एक लाख करोड़ रुपए का है। इसके मुकाबले भारत सरकार ने इस साल बजट में एआई के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सोचें, कहां छह लाख और एक लाख करोड़ और कहां एक हजार करोड़! दुनिया के एआई पेटेंट में भारत का हिस्सा सिर्फ 0.39 फीसदी है तो चीन का हिस्सा 70 फीसदी है।

भारत सरकार एक हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है लेकिन देश के अरबपतियों ने लाखों करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। इतना बड़ा ऐलान है कि अमेरिका और चीन भी चित हो जाएं। अडानी समूह ने अगले 10 साल में 18 लाख करोड़ तो अंबानी समूह ने सात साल में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का ऐलान किया है। सोचें, यह रकम पढ़ कर लगेगा कि अब भारत एआई क्रांति का विश्वगुरू बनने वाला है। भारत को कोई नहीं रोक सकता है। यह भी भाव मन में पैदा होगा कि अमेरिका और चीन भारत के इन दो कारोबारियों के सामने क्या हैं।

अब सवाल है कि क्या ये दोनों कारोबारी किसी एआई प्लेटफॉर्म का निर्माण करेंगे, क्या ये कोई चैटजीपीटी जैसा बना देंगे और भारत के लोग उसका इस्तेमाल करने लगेंगे? हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि भारत के अंबानी और अडानी कुछ ऐसा बना देंगे, जिसका इस्तेमाल अमेरिका या यूरोप के लोग करने लगेंगे लेकिन क्या भारत के लोगों के लिए भी ये कंपनियां कुछ बना पाएंगी? इनका इतिहास देखते हुए लग नहीं रहा है कि ये कुछ बनाएंगी। इन्होंने एआई क्रांति की फसल काटने का बंदोबस्त किया है। टाटा से लेकर अंबानी, अडानी तब सबने किसी न किसी अमेरिकी कंपनी के साथ तालमेल कर लिया है।

ये लोग उनके वेंडर की तरह काम करेंगे। भारत में सेक्टर स्पेशिफिक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके इस्तेमाल की फीस वसूल कर कमाई करेंगे। उस कमाई का भी बड़ा हिस्सा अमेरिका जाएगा।

अब सवाल है कि भारत की कंपनियां इतना रुपया किस चीज में निवेश करेंगी? भारत की कंपनियों का निवेश जमीन अधिग्रहण करने, उस पर बड़ी इमारतें बनवाने और वहां एआई के डेटा सेंटर स्थापित करके उन्हें चलाने में खर्च होगा। वे बुनियादी ढांचा तैयार करके अमेरिकी कंपनियों को देंगी ताकि वे अपना डेटा सेंटर स्थापित करें। यह बहुत दिलचस्प संयोग है कि भारत सरकार ने इस साल बजट में डेटा सेंटर को 21 साल तक के लिए टैक्स छूट देने की घोषणा की है। यानी विशाल डेटा सेंटर बनेंगे और सरकार को कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाली बिजली आम इस्तेमाल से 40 फीसदी सस्ती होगी। कंपनियां बजट में मिली इस छूट का लाभ उठाएंगी।

ध्यान रहे भारत में डेटा कैपिसिटी अभी 1.2 गीगावॉट की है जो अगले चार साल में बढ़ कर पांच गीगावॉट होने वाली है। इसके लिए 20 से 30 गीगावॉट बिजली की जरुरत होगी और इसी अनुपात में डेटा सेंटर्स की कूलिंग के लिए अरबों लीटर पानी की जरुरत होगी। इस तरह भारत अपनी जमीन देगा, टैक्स छूट देगा, सस्ती बिजली देगा, पानी देगा और सस्ता मानव संसाधन देगा, जिस पर प्राइमरी कमाई अमेरिकी कंपनियों की होगी और उसके बाद उनकी पिछलग्गू भारतीय कंपनियों की कमाई होगी। एक आर्थिक जानकार ने बहुत अच्छा समझाया कि अमेरिका ने कोका कोला और पेप्सी बनाई तो जापान और दक्षिण कोरिया ने रेफ्रिजेरेटर बनाए फिर दोनों ने मिल कर दुनिया भर के देशों से खरबों डॉलर की कमाई की। एआई क्रांति में भी यही होता दिख रहा है। अमेरिकी कंपनियों ने एआई प्लेटफॉर्म बनाए और भारत के अरबपति उनके वेंडर बन कर उनके लिए डेटा सेंटर बना रहे हैं और दोनों मिल कर कमाई करेंगे। इसमें भारत का अपना कुछ नहीं होगा। भारत ने जब किसी क्रांति में कोई हार्डवेयर नहीं बनाया तो सॉफ्टवेयर क्या बनाएगा? भारत एक बढ़िया कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं बनाता है। भारत एक बढ़िया स्मार्ट फोन नहीं बनाता है। भारत अपना टेलीवेजिन सेट या रेफ्रेजेरेटर, एसी और वॉशिंग मशीन नहीं बनाता है। भारत के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वर्ड से लेकर लाइनक्स और आयोस से लेकर एंड्रॉयड तक सब विदेशी है। फिर हम कैसे यह कल्पना कर रहे हैं कि भारत कोई एआई का लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बना लेगा? भारत जैसे पहले कुछ नहीं कर सका और यूजर या इंटरमीडियरी बना रहा वैसे ही आगे भी बना रहेगा। वैसे भी किसी होड़ में क्यों पड़ना है। जैसे बाकी चीजें खरीद कर भारत इस्तेमाल करता है वैसे ही एआई का भी करेगा।

आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना पेश करती है टियांजिन बिनहाई लाइब्रेरी

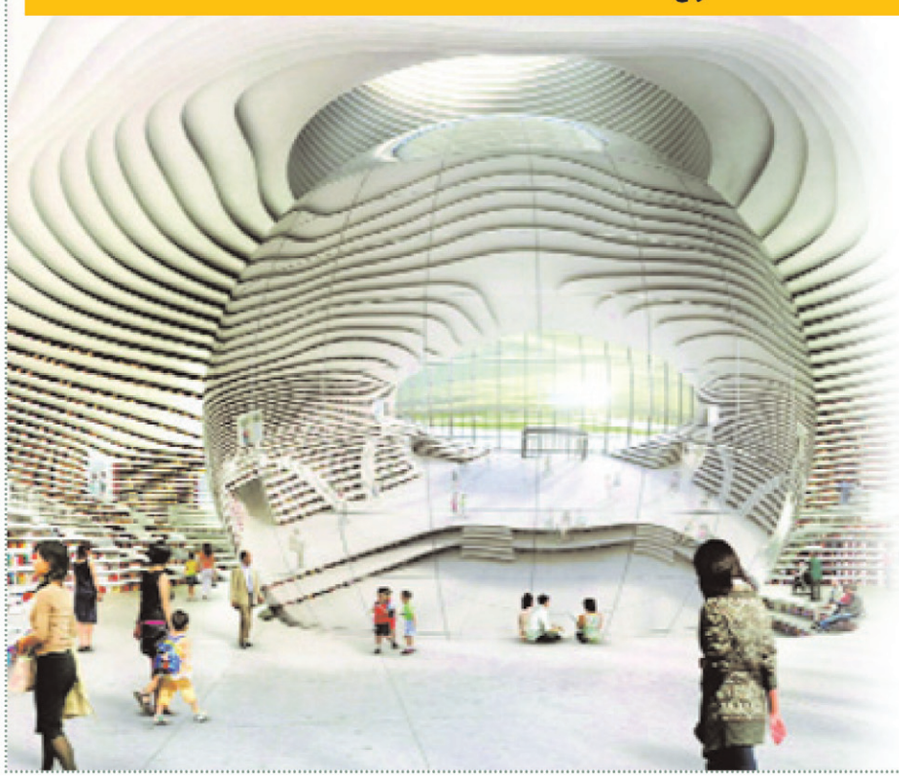

चीन में एक ऐसी लाइब्रेरी है, जिसे देखने के बाद आपकी निगाहें उसी पर टिकी रहेंगी। आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना पेश करती इस लाइब्रेरी का नाम है 'टियांजिन बिनहाई लाइब्रेरी' जिसकी खूबसूरती देख आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, कि ये एक लाइब्रेरी है। यहां कुछ लोग तो सिर्फ फोटो के लिए ही इस लाइब्रेरी का रूख करते हैं। बता दें, इस लाइब्रेरी को चीन के 'नेशनल डे' को आम जनता के लिए खोला गया है। 37, 000 स्क्वायर फीट तक फैली टियांजिन बिनहाइ लाइब्रेरी में हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस लाइब्रेरी की उंचाई करीब पांच मंजिल के बराबर बनी हुई है। यहां पर पढ़ने के लिए हर जॉनर करीब 12 लाख से भी ज्यादा किताबें मिल जाएगी। इस लाइब्रेरी में लगभग हर जॉनर में 12 लाख किताबें हैं। इस लाइब्रेरी को बिनहाई कल्चरल सेंटर में खोला गया है, जिसे डच कंपनी एमवीआरडीवी ने डिजाइन किया है। इस खूबसूरत चीन की लाइब्रेरी में एक बेहद ही यूनिक डिजाइन दिया गया है, जिसमें एक बड़ी आखं बनी हुई है, इस आंख के डिजाइन पर अंदर होने वाली चीजों और बाहर बने पार्क की परछाई पड़ती रहती है, जो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है।

- इस लाइब्रेरी में तकरीबन हर जॉनर की 12 लाख किताबें हैं.
- शहर के बिनहाइ कल्चरल सेंटर में खुले इस लाइब्रेरी को डच कंपनी एमवीआरडीवी ने डिज़ाइन किया है.
- इस लाइब्रेरी में सर्विस स्पेस, बुक स्टोरेज, आर्काइव, कंप्यूटर रूम, ऑडियो रूम, ऑडिटोरियम, लाउंज, मीटिंग रूम, ऑफिस और रीडिंग स्पेस भी हैं.
- इन किताबों और लाइब्रेरी के बीच एक बहुत बड़ी आंख भी बनी हुई है. – इस आंख पर अंदर होने वाली चीज़ों और बाहर बने पार्क की परछाई पड़ती रहती है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है.
- इसे चीन के नेशनल डे पर आम जनता के लिए खोल दिया गया.

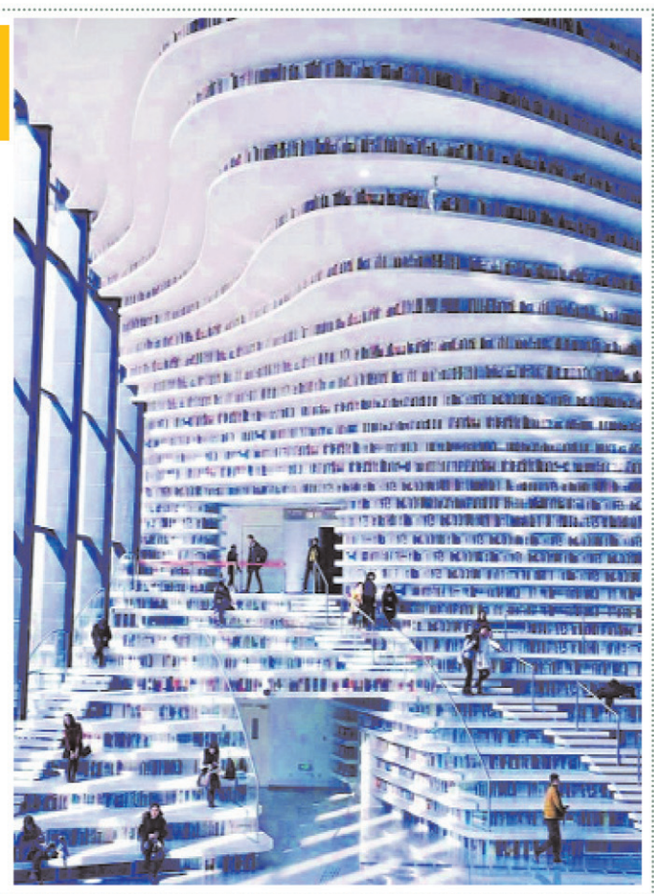

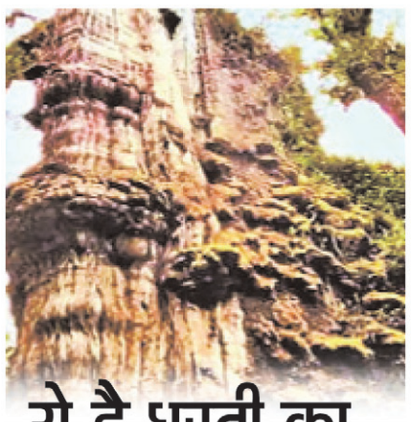

ये है धरती का सबसे पुराना पेड़

महाभारत से पहले का है इसका इतिहास

इस दुनिया में एक नहीं बल्कि कई सारी गजब की जगह और चीज मौजूद है जो लोगों को हैरान कर देती है। पेड़ हम इंसानों के लिए कितने जरूरी हैं यह बात तो सभी जानते हैं। अगर इस धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो इंसान का जीना संभव नहीं है। जब भी पुराने पेड़ों की बात निकलती है तो अक्सर लोगों को बरगद का पेड़ याद आता है। लोग यही कहते हैं की बरगद के पेड़ सालों साल जीते हैं और यह सबसे पुराने होते हैं। लेकिन आज हम आपको इस दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के बारे में बताते हैं जो हजारों साल पुराना है। दुनिया के इस सबसे पुराने पेड़ की बात करें तो यह चिली में पाया गया है, जो लगभग 5000 साल से ज्यादा पुराना है। साइप्रस ट्री के नाम से पहचाने जाने वाला यह पेड़ ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से प्रसिद्ध है। वैज्ञानिकों ने इसलिए नाम इसलिए दिया है क्योंकि यह धरती पर मौजूद सबसे पुराना पेड़ है।

कितने साल का है पेड़

इस पेड़ की उम्र की बात करें तो यह 5484 साल का है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि यह 6000 साल से ज्यादा पुराना है। यह 13 फिट चौड़ा और 28 मीटर लंबा है। इस पर लगातार शोध चल रहा है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसने जलवायु परिवर्तन के साथ खुद को किस तरह से अनुकूल रखा।

हासिल किए ये खिताब

ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ चिली के एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में मौजूद है। जिस कैलिफोर्निया के पाइन पेड़ को हराकर सबसे पुराना पेड़ होने का खिताब अपने नाम किया है। धरती के इस सबसे पुराने पेड़ में लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। अक्सर लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं।

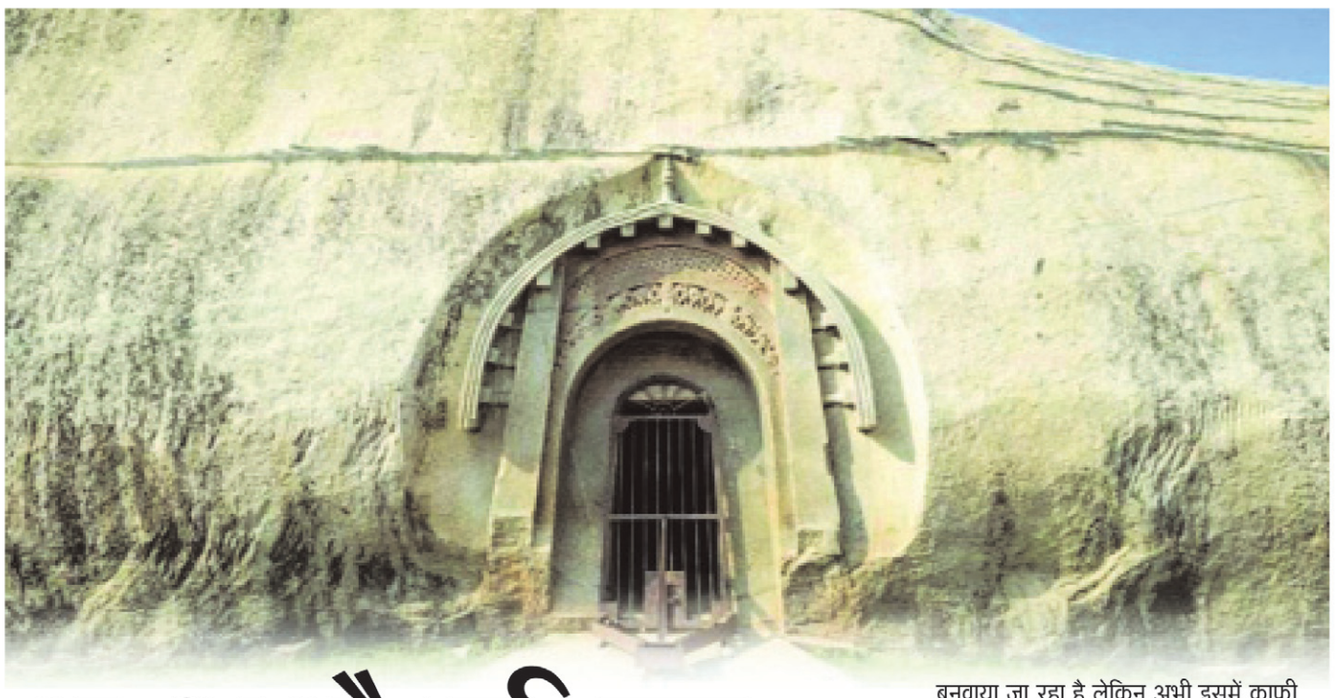

आस्था और इतिहास का खूबसूरत संगम है वाणावर की गुफाएं!

आप सभी जानते होंगे कि पहले आदिमानव के जमाने में गुफाएं उनके रहने का स्थान हुआ करती थी। वह समय ऐसा था जब गुफाएं उन लोगों के लिए एक सुरक्षित घर हुआ करती थी। इतना ही नहीं गुफाएं अलग-अलग मौसम से बचाने का काम करती थी। जंगली जानवर से लोगों की रक्षा किया करती थी। उन गुफाओं के बारे में जानना और वहां जाना अपने आप में बहुत खास है। आज हम एक ऐसी गुफाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो आस्था और इतिहास का एक खूबसूरत संगम है। वह गुफा है वाणावर की गुफाएं।

वाणावर की गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है। वाणावर की पहाड़ियों पर स्थित यह गुफाएं भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। यह गुफाएं तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी और अजीब संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रय स्थल थी।

गुफाओं के पास है सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर

वाणावर की गुफाओं में एक शिव मंदिर भी स्थित है। जिसे सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर सातवीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह बिहार के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। यह वाणावर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सावन के महीने में इस मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। वैसे तो प्रत्येक दिन लोग यहां जल चढ़ाने आते हैं। लेकिन सावन के महीने में यहां का वातावरण ही कुछ और होता है।

वाणावर गुफाओं की विशेषताएं

- वाणावर की गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित है। इन गुफाओं में कुल सात गुफाएं हैं। इनमें से चार गुफाएं वाणावर पहाड़ियों पर और तीन गुफाएं नागार्जुन पहाड़ियों पर स्थित है।
- इन गुफाओं की दीवारों पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण शिल्प और मूर्तियां हैं। इनमें से कुछ शिल्प और मूर्तियां इतनी सुंदर है कि वह आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करती है।
- इन गुफाओं में बुद्ध, बुद्धिसत्व और अन्य बौद्ध देवताओं की मूर्तियां है इनके अलावा इन गुफाओं में कई अन्य शिल्प भी है जिनमें पशुओं, पक्षियों और फूलों की मूर्तियां आदि शामिल है।
- दिन पर दिन इन गुफाओं को और भी ज्यादा सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए सरकारी स्तर पर काम चल रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है।
- यहां हर साल वाणावर महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में लोग बढ़ चढ़कर कर हिस्सा लेते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने में लोगों को आसानी हो इसके लिए रोपवे भी बनवाया जा रहा है लेकिन अभी इसमें काफी समय लग रहा है।

वाणावर की गुफाओं का महत्व

वाणावर की पहाड़ियों पर कुल सात गुफाएं है जिसे देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। यह गुफाएं प्राचीन इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। गुफाओं में मौजूद शिल्प और मूर्तियों से हमें बौद्ध धर्म के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान होती है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहां हर साल हजारों लोग इन गुफाओं को देखने और उनकी प्राचीन संस्कृति और इतिहास को जानने के लिए दूर-दूर से आते हैं। इन गुफाओं को हजारों साल पहले पहाड़ों को सावधानी से काटकर बनाया गया था। इन गुफाओं की दीवारें बहुत चिकनी है। आपको बता दें, इन गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए करवाया गया था। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर ही सम्राट अशोक के अभिलेख है। यह लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, जिसे गाइड पढ़कर विस्तार से बताते और समझाते हैं।

सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई थीं गुफाएं

वाणावर की पहाड़ियों पर कुल सात गुफाएं हैं, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। इनमें चार वाणावर पहाड़ियों पर और तीन पास में ही नागार्जुन की पहाड़ियों पर हैं। पहाड़ों को सावधानी से काट कर हजारों साल पहले इंसान इस बेहद सुंदर गुफाओं को बनाया। इनमें से कई गुफाओं की दीवारों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसकी चिकनाई आज के समय में लगाई जाने वाली टाइल्स से कम नहीं है। मौर्य काल की यह स्थापत्य कला पर्यटकों को आश्चर्य से भर देती है। इनका निर्माण सम्राट अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए करवाया गया था। इसमें कर्ण चौपर, सुदामा और लोमस ऋषि गुफा अपनी स्थापत्य कला के लिए देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर ही सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। ब्राह्मी लिपि के जानकार इसे पढ़ और समझ पाते हैं। गाइड इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

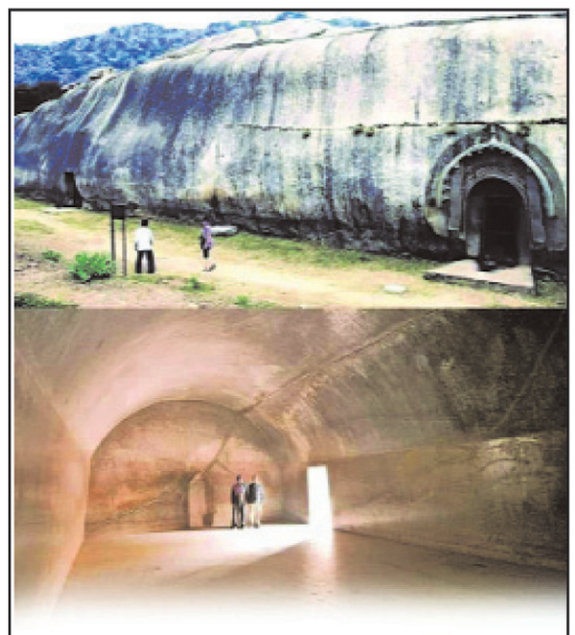

इन गुफाओं में है मौर्यों का खजाना, आज भी दबे हैं यहां कई रहस्य

बिहार की धरती काफी ऐतिहासिक रही है। इस धरती पर जहां कई शूरवीरों ने जन्म लिया और एक नई इबारत लिखी,वहीं प्राचीनता की बात करें तो बिहार में कई ऐसी धरोहर हैं, जो दुनिया भर में लोकप्रिय रही हैं। इन्हीं में से एक धरोहर है बराबर की गुफाएं। ये गुफा भारत की ऐसी सबसे पुरानी गुफा है जो चट्टानों को काटकर बनाई गई है। यही नहीं, इनमें मौर्य काल की वास्तुकला और शिलालेख आज भी मौजूद हैं।

कहां है ये गुफाएं...

- ये गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- इन गुफाओं को 'सतघरवा' भी कहते हैं। इनमें से ज्यादातर का संबंध मौर्य काल (322-185 ईसा पूर्व) से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है।
- ये गुफाएं बराबर (चार गुफाएं) और नागार्जुनी (तीन गुफाएं) की जुड़वां पहाड़ियों में स्थित हैं।
- अधिकतर गुफाएं दो कक्षों की बनी हैं जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराशकर बनाया गया है।

कौन-कौन सी हैं गुफाएं...

बराबर पहाड़ी में हैं ये चार गुफाएं...

- लोमस ऋषि गुफा
- सुदामा गुफा
- करण चौपर
- विश्व जोपरी

नागार्जुन गुफा

- गोपी गुफा
- भायक गुफा
- वैदंतिका गुफा

अन्दर से कैसी हैं बराबर गुफाएं...

गुफाओं की एंट्रेंस वॉल और दरवाजों पर कई शिलालेख हैं, जो बताते हैं कि यहां कभी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ये गुफाएं मगरमच्छ के समान नज़र आने वाली चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। गुफाओं में बने कमरे के इंटीरियर में पॉलिश है, जो आज भी सुरक्षित है।

चट्टानों को काटकर बनाए गए कमरे

चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कमरे अशोक (273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व) और उनके पुत्र दशरथ के मौर्य काल, तीसरी सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। यद्यपि वे स्वयं बौद्ध थे लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों को पनपने का अवसर दिया।

इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के संन्यासियों द्वारा किया गया था जिनकी स्थापना मक्खाली गोसाला द्वारा की गयी थी, वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे।

खबर-खास

घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर खाद्य विभाग की कार्रवाई

जांजगीर-चांपा (समय दर्शन)। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने तथा घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग की टीम द्वारा जिले के लगातार छापामार कार्यवाही की जा रही है।

जिला खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू ने बताया तहसील बलौदा के ग्राम पंचायत पहरिया के विजय स्वीट्स में छापामार कार्यवाही की गई। मौके पर विजय स्वीट्स के संचालक शंकर लाल कुम्भकार के द्वारा घरेलु लाल सिलेंडर का उपयोग व्यवसायिक रूप से नाश्ता तैयार कर व बिक्री करते पाया गया। मौके पर जांच दल के द्वारा 04 नग लाल घरेलू सिलेंडर, 02 नग चुल्हा, 01 नग दोसा प्लेट चुल्हा, 03 नग रेग्यूलेटर एवं 03 नग गैस पाइप की जब्ती की कार्यवाही की गई। उक्त प्रतिष्ठान में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

खाद्य विभाग द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच

दुर्ग (समय दर्शन)। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों एवं संभावित आपूर्ति दबाव को दृष्टिगत रखते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक एवं अन्य अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा 12 मार्च 2026 को जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जाँच की गयी। जाँच में दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में दोसा किंग, अग्रसेन चौक से 3 नग, मुकेश फ़ास्ट फूड सेंटर पोलसाय पारा से 2 नग घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किया गया। इसके अतिरिक्त भिलाई नगर निगम क्षेत्र में दुर्गा मिष्ठान भंडार से 01 तथा शिव प्रसाद भोजनालय सुपेला से 3 नग घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर जप्त किया गया। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर नियंत्रण हेतु जिले में जांच एवं कार्यवाही की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

झूलेलाल जन्मोत्सव पर दुपहिया वाहन रैली व शोभायात्रा

जगदलपुर। सिन्धी गुरुद्वारा कमेटी अध्यक्ष सुंदर भोजवानी ने जानकारी दी श्री गुरु सँगत गुरुद्वारा कमेटी व सिन्धी पंचायत तत्वाधान में समाज सदस्यों की बैठक सिन्धी गुरुद्वारा में आहूत की गई। इस वर्ष 20 मार्च साईं झूलेलाल जी जन्मोत्सव की तैयारी संबंधित बैठक में निर्णय लिया गया, श्री गुरुग्रंथ पाठ साहिब 14 मार्च शनिवार प्रात: 10 बजे से गुरुद्वारा में आरम्भ होगा. साईं झूलेलाल जन्मोत्सव की पूर्व संध्या में 19 मार्च संध्या 7 बजे से भजन कीर्तन व भक्ति संगीत संध्या आयोजन होगा सिंधु भवन में, धमतरी से आए भाई साहब हितेश जग्यासी, रोशनी जग्यासी द्वारा भजन कीर्तन होने के पश्चात भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। गुरुद्वारा कमेटी सचिव संतोष बजाज ने बताया साईं झूलेलाल अवतरण दिवस एवं सिन्धी नव वर्ष में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुबह 9:30 बजे से सिन्धी समाज सभी सदस्य, युवा मंडल, सुहिणी सोच महिला विंग भगवा रंग के वस्त्र में दुपहिया वाहन रैली में शामिल होंगे. यह दुपहिया वाहन रैली सिन्धी गुरुद्वारा से निकलकर चाँदनी चौक, शहीद पार्क चौक, कोतवाली चौक, गोल बाजार, सिरहासार चौक, माँ दंतेश्वरी मंदिर, संजय बाजार, गुरु गोविन्द सिंह चौक, चाँदनी चौक होते हुवे रैली सिन्धी गुरुद्वारा पहुंचेगी. पुरे मार्ग में साईं झूलेलाल की के जयघोष की पुकार होंगी। सिन्धी गुरुद्वारा में 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 11 बजे से भक्ति संगीत के पश्चात श्री गुरुग्रंथ पाठ साहिब समाप्ति व अरदास, पल्लव, भोग साहिब, प्रसादी वितरण होगा। सिंधु भवन में दोपहर 2 बजे से आम लंगर होगा एवं शाम 6 बजे सिन्धी गुरुद्वारा में बहराणा साहिब जी की पूजा समाज सदस्यों द्वारा की जाएगी साथ ही प्रसादी वितरण व शीतल पेय थादल वितरित किया जाएगा. साईं झूलेलाल शोभायात्रा में समाज के सभी सदस्य शामिल होकर छेज नृत्य के साथ झूलेलाल मार्ग, कोतवाली चौक, मुख्यमार्ग होते हुवे गोल बाजार, सिरहासार चौक से बलिराम कश्यप चौक से महादेव घाट पहुंचेंगे, पुरे मार्ग में आतिशबाजी व प्रसाद वितरण होगा। घाट में नीचे नदी किनारे बहराणा साहिब की पूजा, अखो, पल्लव कर प्रसाद व खजाना वितरण किया जाएगा. सिंधु भवन में रात 9 बजे से भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी. 20 मार्च चेटीचंड पर्व पर सिन्धी समाज सदस्यों की समस्त दुकाने अवकाश होंगी। सिन्धी पंचायत के दोनों संरक्षक उधाराम मूलचंदानी, गोवर्धन दास नवतानी ने बताया सनातन सिंधु परम्परा अनुसार झूलेलाल (उड़ेरोलाल) जन्मोत्सव के पावन दिवस पर सिन्धी समाज सदस्य जल व ज्योत की पूजा करते हैं।

अवैध रूप से कप सिरप की तस्करी करते एक आरोपी गिरफ्तार, सिंघोड़ा पुलिस एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कार्यवाह

सरायपाली नृपनिधी पाण्डेय (समय दर्शन)। एन्टी नारकोटिक टॉस्क फोर्स द्वारा नशीली दवाओं के अवैध तस्करी पर नियंत्रण व प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। जिले में पुलिस के द्वारा लगातार चेंकिंग कार्यवाही की जा रही है, इसी दरमियान सूचना मिली की ग्रे रंग की होण्डा साईन ओआर 15 एम 1143 ग्रे होण्डा साईन ओआर 15 एम 1143 में अवैध कप सिरप लेकर आ रहा है, कि सूचना से एनएच 53 रोड रेहटीखोल पहूंच कर नाकाबंदी किये जहां कुछ समय बाद एक होण्डा साईन ओआर 15 एम 1143 आया जिसे रोककर नाम पता पुछने पर मोटर सायकल चालक अपना नाम मोहम्मद रियाज पिता मोहम्मद ताज उम्र 46 साल साकिन मोतीझरन थाना धनुपाली जिला संबंलपुर हाल वार्ड नंबर 15 माता दरबार फेगुलाल सोनवानी के मकान बसना थाना बसना जिला महासमुन्द जिसके कब्जे से अपने पास रखे लाल,पीला, सफेद कलर के कपडे के छींटदार थैला के अंदर भारी मात्रा में नशीली टेबलेट और कफ सिरप किमती 5492.88 रूपये एवं परिवहन हेतु प्रयुक्त एक होण्डा साईन ओआर 15 एम 1143 कीमती 15,000 रूपये, कुल जुमला कीमत 20492.88/- रूपये को जप्त किया गया है। नशीली कप सिरप को संबलपुर ओडिशा से बसना महासमुंद लाना बताया द्य आरोपी का कृत्य अपराध धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिर0 किया जाकर थाना सिंघोडा में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण के आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश की कार्यवाही की जा रही है।

मालवाहक वाहनों का उपयोग सवारी ढोने पर न करें,यातायात नियमों के तहत ही जा रही कार्यवाही

गरियाबंद। (समय दर्शन)। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के दिशा-निर्देश में जिले में सुरक्षित यातायात व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पिछले एक सप्ताह से गरियाबंद पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया इस कार्यवाही के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध 43 प्रकरणों में ''ड्रंक एंड ड्राइव'' के तहत अर्थदण्ड की कार्यवाही किया गया। इसी प्रकार माल वाहक वाहनों में सवारी बैठा कर वाहन चलाने वालां के विरूद्ध कार्यवाही के साथ समझाई दिया गया ।गरियाबंद पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें,मालवाहक वाहनों का उपयोग सवारी ढोने के लिए न करें और नशे की हालत में वाहन चलाकर अपनी व दूसरों की जान जोखिम में न डालें। पुलिस का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

बेमेतरा नगरीय क्षेत्र में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू

पूर्व वर्षों की दरों के आधार पर संशोधित दरें निर्धारित, औसतन 46.5 प्रतिशत वृद्धि

बेमेतरा (समय दर्शन)। बेमेतरा नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2025ङ्क26 के लिए जमीन की नई गाइडलाइन दरें निर्धारित कर लागू कर दी गई हैं। उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नई दरों का निर्धारण पूर्व में लागू वर्ष 2019ङ्क20 की गाइडलाइन दरों, प्रस्तावित संशोधनों तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नई दरों के अनुसार नगरीय क्षेत्र में औसतन लगभग 46.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

कार्यालय उप पंजीयक, बेमेतरा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार विभिन्न वार्डों की दरों में आवश्यक संशोधन किया गया है ताकि वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप गाइडलाइन दरें निर्धारित की जा सकें। शहीद हेमू कल्याणी वार्ड में वर्ष 2019ङ्क20 में गाइडलाइन दर 18,500 रुपये थी। 20 नवम्बर 2025 को प्रस्तावित दर 11,400 रुपये (लगभग 38 प्रतिशत कम) रखी गई थी। वर्तमान में संशोधित दर 22,500 रुपये निर्धारित की गई है, जो लगभग 22 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है।

इसी प्रकार शहीद हेमू कल्याणी वार्ड की दूसरी श्रेणी में वर्ष 2019ङ्क20 में दर 31,000 रुपये थी। 20 नवम्बर 2025 को प्रस्तावित दर 25,200 रुपये (लगभग 19 प्रतिशत कम) निर्धारित की गई थी, जिसे संशोधित करते हुए अब 38,000 रुपये तय किया गया है, जो लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। रानी लक्ष्मी बाई वार्ड में वर्ष 2019ङ्क20 में दर 29,000 रुपये थी। 20 नवम्बर 2025 को प्रस्तावित दर 37,200 रुपये (लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि) निर्धारित की गई थी। वर्तमान में संशोधित दर 58,000 रुपये तय की गई है, जो लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। इस वार्ड की संबंधित कैटेगरी में पूर्व में गाइडलाइन दर का उल्लेख नहीं होने के कारण दरों का पुन: समायोजन किया गया है। बाबासाहेब वार्ड में वर्ष 2019ङ्क20 में गाइडलाइन दर 65,000 रुपये थी। 20 नवम्बर 2025 को प्रस्तावित दर 37,200 रुपये (लगभग 42 प्रतिशत कम) रखी गई थी, जिसे संशोधित करते हुए अब 84,000 रुपये निर्धारित किया गया है। यह लगभग 29 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार मरिजज वार्ड में वर्ष 2019ङ्क20 में गाइडलाइन दर 74,000 रुपये थी। 20 नवम्बर 2025 को प्रस्तावित दर शून्य रखी गई थी क्योंकि उस समय रोड श्रेणी के अंतर्गत नया परिसीमन नहीं हुआ था। वर्तमान गाइडलाइन में वर्ष 2019ङ्क20 की रोड दर को आधार मानते हुए संशोधित दर 88,800 रुपये (लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि) निर्धारित की गई है।

अफीम जैसी घटनाओं से सबक ले भाजपा छत्तीसगढ़ में साफ छवि वाले कार्यकर्ताओं को ही मिले संगठन की जिम्मेदारी

मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक पदाधिकारियों की नियुक्ति से पहले हो ग्राउंड रिपोर्ट, माफिया और ठेकेदार लॉबी से जुड़े चेहरों को संगठन से दूर रखने की उठ रही मांग

अहिवारा (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ में हाल के वर्षों में सामने आई विवादित घटनाओं और संगठन से जुड़े कुछ नेताओं पर लगे आरोपों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने संगठनात्मक शुचिता की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों और जमीनी कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि भाजपा को भविष्य में अफीम प्रकरण जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचना है, तो उसे मंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक पदाधिकारियों की नियुक्ति से पहले उनकी ग्राउंड रिपोर्ट और सामाजिक छवि की गंभीर जांच करनी होगी।

संगठन की साख पर सवाल

छत्तीसगढ़ में भाजपा लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण मजबूत संगठन वाली पार्टी मानी जाती रही है। लेकिन समय के साथ संगठन में ऐसे लोगों की घुसपैठ की चर्चा भी बढ़ी है, जिनका राजनीतिक जीवन सामाजिक सेवा से अधिक खनन, ठेकेदारी और व्यापारिक हितों से जुड़ा रहा है। पार्टी के भीतर ही यह आवाज उठ रही है कि आज भी कई जिलों में खनन माफिया, चावल माफिया और बड़े ठेकेदारों से जुड़े लोग संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, जिससे भाजपा की साफ-सुथरी छवि प्रभावित हो रही है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि संगठन में ऐसे तत्वों का प्रभाव बढ़ता रहा, तो इससे भाजपा के मूल कार्यकर्ता हाशिए पर चले जाएंगे और पार्टी की विचारधारा आधारित राजनीति कमजोर होगी।

मंडल से प्रदेश तक हो सख्त स्क्रीनिंग

राजनीतिक विश्लेषकों का सुझाव है कि भाजपा को संगठनात्मक नियुक्तियों में तीन स्तर की जांच प्रणाली लागू करनी चाहिए— मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की सामाजिक छवि और सार्वजनिक व्यवहार का मूल्यांकन। जिला स्तर पर आर्थिक और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच। प्रदेश स्तर पर संगठन के वरिष्ठ नेताओं द्वारा स्वतंत्र ग्राउंड रिपोर्ट। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि संगठन में वही लोग आगे आएं जो सामाजिक रूप से स्वच्छ छवि, जनसेवा और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता रखते हों। भाजपा के कई पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्षों तक पार्टी के लिए काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर धनबल और बाहुबल वाले लोगों को पद दिए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो इससे संगठन की जड़ें कमजोर होंगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भाजपा का मूल आधार राष्ट्रवाद, संगठन और सेवा की राजनीति रहा है। इसलिए संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि— पदाधिकारियों का चयन विचारधारा और कार्यकर्ता जीवन के आधार पर हो। आर्थिक और आपराधिक विवादों से जुड़े लोगों को संगठनात्मक जिम्मेदारी न दी जाए।जमीनी स्तर पर सक्रिय और सामाजिक रूप से सम्मानित लोगों को आगे लाया जाए। छत्तीसगढ़ की राजनीति तेजी से बदल रही है और आने वाले वर्षों में राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है। ऐसे में यदि भाजपा अपने संगठन को साफ-सुथरे और समर्पित नेतृत्व के साथ पुनर्गठित करती है, तो यह न केवल पार्टी के लिए बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिए भी सकारात्मक संकेत होगा।

खाद घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की जाए:- विधायक यास

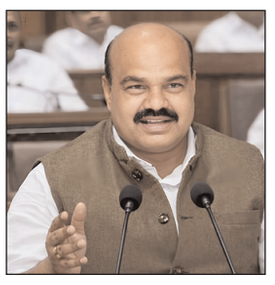

जांजगीर(समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आठवें दिन कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं आदिम जाति विकास विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए जांजगीर-चांपा विधायक ब्यास कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आत्मा खेती-किसानी पर ही बसती है और हम अधिकांश किसान यहां पर चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हों, सबका मूल व्यवसाय खेती-किसानी ही है। मैं स्वयं पहले एक किसान हूं, बाद में विधायक हूं। खेती मेरी पहचान है और मिट्टी मेरी आत्मा, इसलिए किसान की सिसकियों को मैं अपनी मेज पर महसूस करता हूं। उन्होंने कहा कि खाद-बीज की कमी एवं कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। सरकारी सोसायटियों में यूरिया का स्टॉक खत्म बता दिया जाता है जबकि वही यूरिया खुले बाजार में 1500 रूपए प्रति बोरा तक बिका है। राज्य के खाद वितरण की नोडल एजेंसी मार्कफेट के द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय कारखानों को दरकिनार कर राजस्थान की एक प्रायवेट कंपनी के खाद को सोसायटियों में भर-भरकर बिकवाया। उसके द्वारा मोटा कमीशन लेकर राजस्थान की कंपनी को लाभ पहुंचाया गया है। मार्कफेड का सिंगल सुपर फास्फेट खाद में कमीशन किसी से छिपा नही है। सहकारी समिति के लिए इसकी किमत 500 रूपये तय की गई है जबकि खुले बाजार में यह 450 रूपए में मिल जाता है क्या पिछले साल डी.ए.पी. के बदले तीन बोरी एस.एस.पी. इसी कमीशन के लिए बिकवाया गया। उन्होंने राजस्थान की प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने वाले अधिकारी एवं मार्कफेट खाद घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मैं जांजगीर-चांपा जिले से आता हूं, वहां के साथ-साथ पूरे राज्य में धान का उत्पादन घट गया है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सरकार इस बार 149 लाख मीट्रिक टन के बदले 141 लाख मीट्रिक टन ही धान खरीद पाई है। प्रमाणित आंकड़ों में वर्ष 2024-25 में 149 लाख मीट्रिक टन रह गया है। जांजगीर-चांपा में भी उत्पादन साढ़े छ: लाख से गिरकर 6 लाख 10 हजार मीट्रिक टन पर आ गया है। यह गिरावट प्रमाणित करती है कि खाद नही मिलने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं जांजगीर-चांपा जिले से आता हूं। पिछली सरकार के समय 184 करोड़ रूपये का ऋण वितरण हुआ था जो इस सरकार में घटकर 164 करोड़ रूपए रह गया है। जिला सहकारी बैंक बिलासपुर में यू.पी.आई. नही होने से उपभोक्ताओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि छ.ग. की वर्तमान सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम बदलकर कृषक उन्नति योजना तो कर दिया गया, लेकिन बोनस का पैसा देने में बैंक असमर्थ हैं। उन्होंने फसलों के लिए यूरिया, पोटाश, डी.ए.पी. के साथ-साथ जिंक मैंगनीज एवं माइक्रो न्यूट्रिशन वाले खाद प्रदान करने पर भी जोर दिया। वरना पौष्टिक आहार नही मिलने से आने वाली पीढ़ी मेडिकल स्टोर पर मल्टीविटामिन की गोलियां ढूंढते रह जायेंगे। उन्होंने दलहनी-तिलहनी खेती के लिए भी जोर देने तथा उसके लिए एम.एस.पी. के अनुसार भुगतान करने पर जोर दिया।

कांग्रेस बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को बढ़ाने की कमर

बीजेपी कमल के साथ अफीम की खेती कर रह है-चावला

गरियाबंद (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेशभर में जिला संगठन के मार्गदर्शन में पंचायत और बूथ का गठन करने का फैसला लिया है। जिले में ब्लॉक कमेटियों तक का गठन तो हो चुका है, मगर अधिकतर जगह बूथ कमेटियों का गठन बचा हुआ है ।इसी तरह बनाए जा रहे ग्राम पंचायत स्तर पर कांग्रेस अध्यक्ष का भी मनोनयन अब तक नहीं हो सका है ।इसे ध्यान में रख कर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिलों का प्रभारी बना कर उन्हें तत्काल प्रभाव से जल्द ही जिलों का दौरा कर जिला कांग्रेस कमेटियों की मीटिंग लेने को कहा गया है,जिससे चुनाव की प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके ।यह भी कहा गया है कि जिला कांग्रेस कमेटी से कहा जाए कि ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रभारियों का गठन करें और जिले के प्रमुख नेताओं,विधायकों,पूर्व विधायकों को बूथ कमेटी बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। इसके जरिए यह तय किया जा रहा है कि विधायक या पूर्व विधायक की निगरानी में बने बूथ मजबूत रहेंगे और चुनाव के वक्त इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखने कहा गया है कि बूथ कमेटी का गठन उसी बूथ में बैठक कर किया जाएगा और वहां बूथ के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सर्वसम्मति से मनोनयन किया जाए ।इन्हीं सब विषयो पर गुरुवार को जिला कांग्रेस भवन में पूर्व प्रभारी मंत्री संगठन छत्तीसगढ़ एवं महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अमरजीत चावला द्वारा जिला अध्यक्ष,ब्लाक अध्यक्ष शहर अध्यक्ष व जिला पदाधिकारियों बैठक लेकर दिशानिर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता को तैयार होना है,और जनता तक कांग्रेस के इस बात को पहुंचाना है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के धान के दाम बढ़ाकर पूरा धान खरीदे,स्कूल खुलवाए,लेकिन बीजेपी कमल के साथ अफीम की खेती को बढ़ावा दे रहा है,अपराध दुर्घटना बढ़ी,महिलाओ का सम्मान नहीं हो रहा है ।लेकिन हमें अब आपसी भाई चारा बढ़ाकर संगठन में मजबूती लाना है तब पार्टी सत्ता में आएगा ।साथ ही उन्होंने 17 मार्च को होने वाला विधानसभा घेराव की रूपरेखा तैयार करने और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता लाने की बात जिला संगठन को कहा ।वही उन्होंने जिला अध्यक्ष को पंचायत और बूथ का गठन में महिलाओं को प्राथमिकता,उनकी सम्मान बढ़ाकर जोड़ने और आरक्षण को विशेष ध्यान में रखना का निर्देश दिए ।आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के षडयंत्र से लड़ना है ।जिला में वार्ड के अनुसार संगठन को बनाना है ।कांग्रेस तो समुंदर की तरह है कई आते है कई जाते है इन बातों को नजरअंदाज करना है ।इस साथ ही उन्होंने शक्त निर्देश देते हुए कहा कि ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष अगर एक बार मिटिंग में नहीं आता तो नोटिश देकर स्पष्टीकरण ले और तीन बार मिटिंग में अनुपस्थित रहे तो उन्हें हटाने का अधिकार जिला अध्यक्ष को दे दियर्गया है ।बैठक के प्रारंभ में जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हमें जनता तक छत्तीसगढ़ के बीजेपी के करतूतों को जनता तक पहुंचाना है, कांग्रेस आम जनता गरीब व किसानों के हित के लिए सोचती है वही बीजेपी पार्टी के कुछ मंत्री नेता नशीली पदार्थों का उपज लेकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

कवर्धा वनमंडल में आई.जी.एन.एफ.ए. देहरादून के 33 प्रोबेशनर्स अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण भ्रमण

कवर्धा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के वर्ष 2025-27 बैच के 33 भारतीय वन सेवा के प्रोबेशनर्स अधिकारियों का छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत कवर्धा वनमंडल में Soil & Water Conservation Measures and Watershed Management E&ercise विषय पर दिनांक 11 से 12 मार्च 2026 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण भ्रमण आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त प्रोबेशनर्स अधिकारियों को चिन्हांकित 04 नालों के लिए पृथक-पृथक 04 समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह द्वारा संबंधित नाले के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए पी.पी.आर./डी.पी.आर. तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एन.आर.एम. इंजीनियर तथा कवर्धा वनमंडल के तकनीकी सहायकों सहित समूहवार अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। दिनांक 11 मार्च 2026 को कवर्धा वनमंडल के सभागार में श्रीमती अजीता लॉगजम (भा.व.से. 2012), निखिल अग्रवाल, वनमंडलाधिकारी, कवर्धा, नवनीत नायक, एन.आर.एम. इंजीनियर, जी.आई.एस. एक्सपर्ट, कैम्पा, समस्त उपवनमंडलाधिकारी तथा अधीक्षक भोरमदेव अभ्यारण्य की उपस्थिति में सभी 33 प्रोबेशनर्स अधिकारियों से सामान्य परिचय प्राप्त किया गया। इसके उपरांत अधिकारियों को Soil & Water Conservation Measures and Watershed Management E&ercise विषय पर गूगल अर्थ एवं क्यू.जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोजेक्ट तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के पश्चात समस्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित समूहों के अनुसार चयनित नालों में जाकर स्थल निरीक्षण एवं ग्राउंड ट्रूथिंग की गई।

अफीम की अवैध खेती को लेकर सियासत गरम, कांग्रेस का जोरदार धरना-प्रदर्शन

भाजपा नेताओं-मंत्रियों पर संरक्षण का आरोप, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

गरियाबंद (समय दर्शन)। प्रदेश में कथित रूप से हो रही नशीली पदार्थ अफीम की अवैध खेती को लेकर सियासत तेज हो गई है इस मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी जिला कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारे बाजी किए और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए ।ज्ञात हो कि प्रदेश कांग्रेस के निदेशानुसार कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ता जिला कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए उसके पश्चात बीजेपी कार्यालय का घेराव करने निकले,लेकिन बीजेपी कार्यालय के पहले ही बेरीकेट्स लगाकर तैयार पुलिस जवानों द्वारा कांग्रेसियों को रोक लिया गया,जहां कांग्रेस और पुलिस जवानों के बीच काफी झुमाझटकी की स्थिति बन गई ।वही कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से नशीली पदार्थों की खेती का मामला सामने आना बेहद चिंताजनक है और यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो इसका सीधा असर प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है लेकिन बीजेपी के राज में हमारा छत्तीसगढ़ नशीली सामान के उपज के लिए प्रचलित हो गा है।

धरना-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कुछ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में अफीम की खेती की जा रही है,लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ।उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धरना-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस मामले में जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के जाल से बचाने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रहेगी।इस दौरान सुखचंद बेसरा,स्मृति ठाकुर, पवन सोनकर आदि उपस्थित थे।

खबर-खास

राजकुमार साहू बने प्रदेश साहू संघ के व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक

जांजगीर चांपा (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू द्वारा समाज के संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। इसी क्रम में व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के रूप में जिला पंचायत सभापति राजकुमार साहू को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह दायित्व मिलने पर राजकुमार साहू ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू सहित संगठन के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि साहू समाज के लोगों को व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने तथा समाज के व्यापारियों को एक मंच पर जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि समाज मे एकता बनी रहे भाई चारा बनी रहे उन्होंने कहा कि समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए व्यापार को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके लिए व्यापार से जुड़े लोगों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय स्थापित कर उन्हें नई मार्ग नई योजनाओं एवं अवसरों की जानकारी भी दी जाएगी।

राजकुमार साहू ने कहा कि संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे तथा समाज के हित में लगातार कार्य करते रहेंगे।

14 मार्च को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

मुंगेली(समय दर्शन)। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया। विशेष रूप से राजस्व मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं, पक्षकारों की सुविधा, न्यायालय परिसर में व्यवस्था तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के विषय में भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर कुन्दन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती कंचन लता आचला तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निराकरण किया जाता है, जिससे आम नागरिकों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त होता है।

ग्राम पोण्डी में 13 मार्च को होगा जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन

बालोद। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं जनशिकायत निवारण विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन बालोद द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु जिला स्तरीय 'जनसमस्या निवारण शिविरों' का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत बालोद विकासखण्ड के ग्राम पोण्डी में 13 मार्च को सुबह 10.30 बजे से शाम 05 बजे तक जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के सफल आयोजन हेतु ग्राम पोण्डी में आयोजित शिविर हेतु अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री नूतन कंवर नोडल अधिकारी एवं जनपद पंचायत बालोद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में प्रत्येक माह न्यूनतम दो जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

होला मोहल्ला की तैयारियों का कलेक्टर ने लिया जायजा

बसना (समय दर्शन)। बसना विकासखण्ड अंतर्गत गढ़फुलझर नानक सागर में आगामी 15 मार्च को होला मोहल्ला का आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर विनय कुमार लंगेह आज नानक सागर पहुंचे। यहां 15 मार्च को श्री गुरूनानक देव जी के ऐतिहासिक स्थल नानक सागर में होला मोहल्ला का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में भव्य गुरूद्वारा अस्पताल एवं यात्री निवास हेतु भूमि पूजन व अरदास भी किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने बताया कि यहां देश विदेश से सीख कमेटियों एवं अन्य प्रमुख दलों को आमंत्रित किया गया है। जिसमें बड़ी संख्या में कमेटियों एवं प्रमुखजन आएंगे। कलेक्टर ने की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया एवं सुरक्षा, बेरिकेटिंग, साफ सफाई, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम बसना हरिशंकर पैकरा सहित सिख समाज के स्थानीय प्रमुख हरजिंदर सिंह , महिपाल सिंह,जगपाल सिंह ,रिंकू ओबेरॉय,चरणजीत सिंह, बलवीर सिंह, मुखविंदर सिंह,रोमी सलूजा, अधिकारी कर्मचारी एवं आयोजन समिति के सदस्य गण उपस्थित थे।

पटरीपार सिकोला भाटा सब्जी मार्केट में निगम की बड़ी कार्रवाई, नाली के ऊपर बने 35 से अधिक अवैध निर्माण तोड़े

दुर्ग/। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर में बढ़ते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पटरीपार सिकोला भाटा सब्जी मार्केट क्षेत्र में नाली के ऊपर किए गए अवैध निर्माणों को हटाया गया। निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से करीब 35 से अधिक दुकानों के बाहर नाली के ऊपर बनाए गए अवैध शेड और पक्के निर्माण को तोड़कर हटाया। बताया गया कि लंबे समय से इस क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा नाली के ऊपर कब्जा कर पक्के निर्माण कर लिए गए थे, जिससे आवागमन और सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इस संबंध में नगर निगम द्वारा पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन अवैध कब्जाधारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

महापौर श्रीमती अलका बाघमार के सख्त निर्देश पर आज अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पटरीपार सिकोला भाटा के कई दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई को देखते हुए स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे का समय भी मांगा। इस पर निगम अधिकारियों ने उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी कि तय समय के बाद यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि शहर क्षेत्र में सड़क और नालियों के ऊपर अवैध रूप से निर्माण कर व्यवसाय करना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शहर के सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा कर व्यवसाय किया जाएगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम द्वारा शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने के लिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सारंगढ़ विधायक उतरी ने कुटेला में अवैध फ्लाईएश डंपिंग मामला उठाया : सरकार ने कहा- नहीं दी गई कोई अनुमति

अगर अनुमति नही तो हजारो टन फ्लाईएश कैसे पाटा गया ?

सारंगढ़-बिलाईगढ़ (समय दर्शन)। रायगढ़ जिले के उद्योगों द्वारा सारंगढ़ क्षेत्र में की जा रही फ्लाईएश (राखड़) की अवैध डंपिंग का मामला अब विधानसभा के गलियारों तक पहुँच गया है। हाल ही में विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्पष्ट किया है कि सारंगढ़ के कुटेला स्थित पुरानी पत्थर खदानों में फ्लाईएश डालने की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है।

?विधायक ने उठाए गंभीर सवाल

?श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े ने सदन में प्रश्न क्रमांक 1646 के माध्यम से आवास एवं पर्यावरण विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। उन्होंने वित्त मंत्री से सीधा सवाल किया कि सारंगढ़ के कुटेला स्थित पुरानी पत्थर खदानों में किसकी अनुमति से फ्लाईएश डंपिंग का कार्य किया जा रहा है? ?उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि इस डंपिंग से स्थानीय जल स्रोतों को भारी नुकसान पहुँच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले ठेकेदारों, उद्योगों और बिना अनुमति कार्य होने देने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

सरकार का जवाबः 'अनुमति है ही नहीं

इस प्रश्न के लिखित जवाब में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के कुटेला में स्थित पुराने पत्थर खदानों में फ्लाईएश डंपिंग के लिए कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सरकार के इस जवाब से यह साफहो गया है कि यदि वहां राखड़ डाली जा रही है, तो वह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का लंबे समय से आरोप रहा है कि रायगढ़ के उद्योगों से निकलने वाली फ्लाईएश को र बिना किसी सुरक्षा मानकों के खाली खदानों में भरा जा रहा है। इससे न केवल हवा प्रदूषित हो रही है, बल्कि बारिश के पानी के साथ मिलकर यह जहरीली राखड़ भूजल स्तर को भी दूषित कर रही है, जिससे भविष्य में जल संकट और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।?

कुटेला पत्थर खदान में फ्लाईएश बिना अनुमति से हजारों टन कई गड्डों को ?बिना अनुमति पाट दिया गया , तो अब प्रशासन और पर्यावरण मंडल पर यह जिम्मेदारी आती है कि वे इस अवैध कार्य को तुरंत रोकें और दोषी उद्योगों व ठेकेदारों पर भारी जुर्माना व कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए लेकिन सवाल यह है की यहाँ तो अधिकारियो की देख रेख मे खुलेआम हुआ है सूत्र की माने तो लाखो रुपए का चढ़ावा कई विभाग और अधिकारियो तक पंहुचा है क्या अब ऐसे मे जिले के कई अधिकारी पर कार्यवाही की गाज

अविवाहित महिला को डराया, नवजात शिशु का किया गर्भपात, गिरफ्तार

बालोंद (समय दर्शन)। थाना प्रभारी डौण्डीलोहारा निरीक्षक मुकेश सिंह एवं स्टाफके द्वारा ग्राम सिवनी हाल निवासी रामनगर डौण्डीलोहारा के अविवाहित महिला को डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर अवैध संबंध बनाकर गर्भ में पल रहे नवजात शिशु को गर्भपात करने के लिए मृतिका/पीडिता को दवाई खिला दिया जिससे अविवाहित महिला एवं गर्भ में पल रहे नवजात शिशु की मौत हो जाने के मामले में बारिकी से विवेचना कार्यवाही किया गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10/03/2026 को थाना डौण्डीलोहारा के मर्ग क्रमांक 17/2026 धारा 194 बीएनएसएस की मृतिका/पीडिता का मृत्यु हो गया है कि सूचना मिलने पर थाना डौण्डीलोहारा पुलिस रवाना हुआ। मौके पर पहुंचकर मृतिका की मां से पुछताछ कर मर्ग इन्टीमेशन लिया जिसमें सूचक द्वारा बताया कि ये अपनी दो बेटी एवं एक बेटा के साथ लगभग 03 वर्षो से डौण्डीलोहारा के सुनील कुमार घरडे के मकान में किराये से रहती है कि दिनांक 09/03/2026 के रात्रि करीबन 09/30 से 10/00 बजे के मध्य लडकी मृतिका/पीडिता के कमर, पेट तथा पैर में दर्द होने लगा तब मकान मालिक सुनील कुमार घरडे के द्वारा गोली (दवाई) को मृतिका/पीडिता को दर्द का गोली है कहकर खिला दिया, जिससे मृतिका/पीडिता छटपटाने लगी व पलंग में चित होकर सो गई कुछ देर में श्वांस चलना बंद हो गया, जिससे मौके पर मृतिका/पीडिता की मृत्यु हो गई थी, जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण व परिवार के सदस्यों व अन्य गवाहों से पुछताछ कथन से पता चला कि मृतिका/पीडिता जो कि कुंवारी थी तथा वह मकान मालिक सुनील कुमार के द्वारा मृतिका/पीडिता को लगभग एक

वर्षों से डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार अवैध शारीरिक संबंध बनाने से वह लगभग 09 माह की गर्भवती थी, आरोपी द्वारा मृतिका व उसके परिवार को अपने किराये के मकान से निकाल देने की धमकी देकर तथा डरा धमका दुष्कर्म को छिपाने का प्रयास किया गया है। आरोपी द्वारा अपराध को छुपाने की नियत से मृतिका/पीडिता को जान बूझकर कोई अज्ञात दवाई को हाथ पैर का दर्द होने का है कहकर खिलाया जिससे मृतिका की मृत्यु हो गया। संपूर्ण मर्ग जांच में अपराध धारा 90,91, 105, 238, 351 (3), 64(2) द्व बीएनएस का पाये जाने से आरोपी सुनील कुमार घरडे के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी को दिनांक 11.03.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

कलेक्टर मिश्रा ने जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम जुंगेरा पहुँचकर डीएमएफबेस लाइन सर्वे कार्य का लिया जायजा

ग्रामीणों से चर्चा कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि बुनियादी सुविधाओं के उपलधता एवं आवश्यकता के संबंध में जानकारी ली

बालोद। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम जुंगेरा पहुँचकर ग्राम पंचायत में चल रहे डीएमएफ बेस लाइन सर्वे कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर जुंगेरा सहित आसपास के गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पेयजल, कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचा की उपलब्धता एवं आवश्यकताओं के

संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार डीएमएफबेस लाइन सर्वे कार्यक्रम अंतर्गत जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, बुनियादी ढांचे की कमियों और पर्यावरणीय मुद्दों का मानचित्रण करना ताकि लक्षित विकास सुनिश्चित करने हेतु बेस लाइन सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर जुंगेरा एवं आसपास के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत मोबाईल वैन के अलावा 108 एवं 102 वाहनों की उलपब्धता, स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयों एवं अन्य जरूरी चीजों की उलपब्धता तथा स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते हुए पालकों तथा शिक्षकों के बीच नियमित रूप से संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

पिथौरा तहसील कार्यालय में स्वच्छता और सुविधाएं भगवान भरोसे

पिथौरा(समय दर्शन)। महासमुन्द जिले में पिथौरा हर दृष्टिकोण से अपना अलग महत्व रखता है। एक तरफ स्वच्छता को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया जो हर जन जन को पसंद आया और लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लेकर स्वच्छता अभियान मे अपनी सहभागिता निभाई और हर गली सड़क गांव शहर में स्वच्छता अभियान चल पड़ा। नगर निगम, पालिका, पंचायत सब जगह स्वच्छता अभियान अनेकों गांव को सरकार ने स्वच्छता अभियान के लिए पुरूस्कार भी दिया ,सम्मान किया, परंतु जनपद पंचायत पिथौरा जिला महासमुन्द के परिसर में स्वच्छता अभियान दम तोड़ रही है। पुष्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां के नगर स्थित शासकीय परिसरों के शौचालयों की महीनो महीनो सफाई नहीं की जाती। शौचालय की गंदगी और बदबू के चलते लोग शौचालय का उपयोग नहीं करते। ऐसा ही हाल तहसीलदार कार्यालय का है, भी जहां शौचालय में दरवाजे ही नहीं है। पानी नहीं है। खास कर शासकीय कार्य से आने वाली महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाखों के राजस्व देने वाली रजिस्ट्री कार्यालय में पेयजल और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

यहां की बदहाल स्थिति यहां के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों, अधिकारी कर्मचारियों के कार्यप्रणाली को उजागर करती है। समाचार के साथ शासन प्रशासन हरकत में आती है,या यहां के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियो के उदासीन रवैए से लोगों को सतत समस्या से जूझना पड़ता रहेगा।

।। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)।।

// ईश्तहार //

प्र.क्र. 202602100600014
अ-2/2025-2026

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक वेद प्रकाश पिता श्री सुरेश कुमार वर्मा, निवासी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा ग्राम अखरा, प.ह.नं. 35 तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 243/22 रकबा 0.0099 हे. भूमि पर आवासीय प्रयोजन में डायवर्सन किए जाने के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 172 के तहत प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो वे स्वयं या विधिक अधिकारिता रखने वाले अपने अभिभाषक (अधिवक्ता) के माध्यम से नियत दिनांक 20.03.2026 तक न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिवस के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति कर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के पद मुदा सहित जारी क्रिया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पाटन, जिला- दुर्ग

// कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) //

// सार्वजनिक सूचना//

कं./न.नि.मि./भ.अ.वि./1403/2026
भिलाई, दिनांक 12/03/2026

स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित जुनवानी भिलाई द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना, स्वीकृत अभिन्यास में छेड़छाड़ कर भूखण्डों का विक्रय करने, स्वीकृत अभिन्यास में खुले क्षेत्र में अवैध रूप से भूखण्ड काटकर विक्रय किये जाने, स्वीकृत अभिन्यास में खुला क्षेत्र, पार्क, स्कूल या मार्ग हेतु सुरक्षित भूमि में से अवैध रूप से भूखण्ड काटकर विक्रय करने के फलस्वरूप स्मृति नगर कॉलोनी का प्रबंध निगम द्वारा अधिग्रहित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292-एफ(2) के प्रावधानों के अधीन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सार्वजनिक सूचना कमशः दिनांक 15.10.2025, 26.11.2025 एवं 15.12.2025 को जारी किया जाकर स्थानीय समाचार पत्रों में विधिवत् प्रकाशन उपरांत दिनांक 12.01.2026, 25.01.2026 एवं 11.03. 2026 को आपत्तियों की सुनवाई की गयी है। दिनांक 11.03.2026 को स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर संस्था को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय चाहा गया है।

उपरोक्त आवेदन दिनांक 11.03.2026 पर समुचित विचारोपरांत आपत्तियों पर सुनवाई हेतु दिनांक 06.04.2026, सोमवार को अंतिम सुनवाई तिथि नियत की जाती है. संबंधित सहकारी संस्था के पदाधिकारी अथवा कोई हितबद्ध व्यक्ति/संस्था, स्वयं या प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

अवैध अफीम खेती मामले में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, भाजपा सरकार पर लगाए संरक्षण के आरोप

दुर्ग (समय दर्शन)। जिले के जेवरा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम समोदा में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार द्वारा अपने फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध अफीम की खेती के मामले को लेकर दुर्ग में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी आक्रामक तेवर में नजर आई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जिला भाजपा कार्यालयों का एक साथ घेराव किया गया, जिसके तहत दुर्ग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।

जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर एवं दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के संयुक्त नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन, दुर्ग से भाजपा कार्यालय घेराव के लिए रैली के रूप में निकले। इस दौरान कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफनारेबाजी करते हुए आगे बढ़े।

भारी पुलिस बल तैनात, कई लेयर में की गई बैरिकेडिंग

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन द्वारा पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। भाजपा कार्यालय जाने वाले मार्ग पर कई लेयर में बैरिकेडिंग कर रास्ते को रोक दिया गया था, ताकि कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय तक न पहुंच सकें।

जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी देखने को मिली। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए एक बैरिकेड तोड़ दिए और मुख्य बैरिकेड तक पहुंचने का प्रयास किया। मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही और पुलिस अधिकारियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रमुख रूप से उपस्थित पूर्व केबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के फार्म हाउस में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी, जो कानून के खिलाफ गंभीर अपराध है। इसके बावजूद भाजपा सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है। जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और भाजपा नेता ही खुलेआम अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्री ठाकुर ने सरकार से सवाल किया की अफीम की इस अवैध खेती में कौन-कौन से मंत्री और अधिकारी शामिल हैं? नव्या मलिक का नाम सरकार की सूची से किसके दबाव में बाहर किया गया?, नव्या मलिक कितनी बार विदेश गई और किन लोगों के साथ विदेश यात्रा की?, भाजपा नेता विनायक ताम्रकार मुख्यमंत्री निवास में कब-कब आया है?, विनायक ताम्रकार के किन-किन नेताओं से संबंध हैं?, क्या भाजपा सरकार विनायक ताम्रकार द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को हटाकर उस पर कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएगी?

दुर्ग शहर अध्यक्ष श्री धीरज बाकलीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेगी और जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक कांग्रेस का जन आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और भी उग्र आंदोलन करने के लिए

विद्युत विभाग के मरम्मत कार्य के चलते कल कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति होंगे प्रभावित

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत बोरसी, पोटिया, पुलगांव, बघेरा, सिकोला बस्ती, कातुलबोर्ड तथा गंजपारा सहित आसपास के क्षेत्रों में 42 एमएलडी इंटेकवेल के माध्यम से फिल्टर प्लांट के जरिए पेयजल आपूर्ति की जाती है। और 24 एमएलडी क्षेत्र में आने वाले पदमनाभपुर टंकी- वार्ड नं. 43 (कसारीडीह, पूर्व), वार्ड नं. 44 (बाबा गुरूघासीदास वार्ड), वार्ड नं. 45 (पद्मनाभपुर पश्चिम), वार्ड नं. 46 (पद्मनाभपुर पूर्व) शंकर नगर टंकी - वार्ड नं. 10 (शंकर नगर, पश्चिम), वार्ड नं. 11 (शंकर नगर, पूर्व), वार्ड नं. 12 (मोहन नगर, पश्चिम), वार्ड नं. 13 (मोहन नगर, पूर्व), शक्तिनगर टंकी - वार्ड नं. 17 (औद्योगिक नगर, उत्तर), वार्ड नं. 18 (औद्योगिक नगर, दक्षिण), वार्ड नं 19 (शहीद भगत सिंह दक्षिण), वार्ड नं. 20 (शहीद भगत सिंह उत्तर), वार्ड नं. 21 (तितुरडीह), वार्ड नं. 22 (स्टेशन पारा) गिरधारी नगर टंकी वार्ड नं. 09 (स्वामी विवेकानंद वार्ड), वार्ड नं. 05 (मरारपारा), हनुमान नगर टंकी - वार्ड नं 19 (शहीद भगत सिंह दक्षिण), वार्ड नं. 20 (शहीद भगत सिंह उत्तर), वार्ड नं. 21 (तितुरडीह), ट्रांसपोर्ट नगर टंकी - वार्ड नं. 16 (करहीडीह) शनिचारी बाजार टंकी- वार्ड नं. 30 (तमेरपारा), वार्ड नं. 31 (आपापुरा), वार्ड नं. 32, वार्ड नं. 33 (चंडीमंदिर), वार्ड नं. 34 (शिव पारा), वार्ड नं. 35 (रामदेव मंदिर), वार्ड नं. 36 (गंजपारा), वार्ड नं. 37 (आजाद वार्ड)।

संक्षिप्त-खबर

आंचल वर्मा करेंगे दुर्ग जिला का प्रतिनिधित्व

पाटन (समय दर्शन)। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित माय भारत के अंतर्गत आयोजित अंतर-राज्यीय युवा आदान-प्रदान एवं विनिमय कार्यक्रम के लिए दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंदर निवासी छात्रा आँचल वर्मा का चयन किया गया है। वे मुंबई में होने वाले इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश तथा दुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह कार्यक्रम 12 से 16 मार्च तक मुंबई में होगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे पढ़ाई जारी है।। और वर्तमान में ग्राम पंचायत पंदर में युवा पंच है।

सेलूद में 5 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ, शिव महापुराण कथा का होगा अप्रैल में आयोजन

पाटन (समय दर्शन)। परम वंदनीया माताजी की जन्म शताब्दी समारोह प्रयाज अभियान के अन्तर्गत आयोजित 5 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ, शिव महापुराण कथा सेलूद (बाजार चौंक) में होगा द्य मंगलमय भगवान आशुतोष महाकाल की कृपा एवं परम पूज्य गुरुदेव वंदनीया माताजी, माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में श्रीमद् शिव महापुराण कथा, 5 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ आयोजित है द्य कथा व्यासपीठ पर आचार्य महादेव जी रायपुर (बंजारी) वाले विराजित होंगे द्य कार्यक्रम दि. 09 अप्रैल 2026, गुरुवार अप. 3 बजे से कलश यात्रा, संध्या 5 बजे संगीत एवं प्रवचन दि. 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार प्रतिदिन प्रात: 9 बजे से 12 बजे तक गायत्री महायज्ञ, 12 से 2 बजे तक भोजन विश्राम, दोप. 2 से 5 बजे तक शिव महापुराण कथा । दि. 12 अप्रैल 2026, रविवार प्रात: 9 से 12 बजे तक गायत्री यज्ञ, 2 से 3 बजे महिला सम्मेलन (मार्गदर्शन गायत्री शक्तिपीठ आमालोरी), 3 से 6 बजे शिव महापुराण कथा, 6 से 7 बजे दीप महायज्ञ, दि. 14 अप्रैल 2026, मंगलवार प्रात: 8 से 12 बजे यज्ञ, 12 से 2 बजे शिवमहापुराण कथा, दोपहर 2 बजे टोली बिदाई, आभार समापन, प्रसादी भंडारा. उक्त अवसर पर पुंसवन, विद्यारंभ, दीक्षा, विवाह दिवस, जन्मदिन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार यज्ञ में नि:शुल्क करायें जायेंगे, जिसका समय पूर्व पंजीयन होगा ।

आज ग्राम सेलूद के कर्मा भवन में बैठक आहूत कर उक्त आयोजन को सफल बनाने के लिए गायत्री शक्ति पीठ आमालोरी के प्रमुख पदाधिकारियो ने मार्गदर्शन दिए जिसमे प्रमुख रूप से कौशल आडिल, अशोक सिंह राजपूत, जगन्नाथ देवांगन, महेश वर्मा, भागवत वर्मा, सियाराम चंद्रकार, लीला सिंह, अजय सिंह ठाकुर, महेश्वर बनछोर, आयोजन समिति के पदाधिकारी सत्यभामा बनछोर, सीता बनछोर, ललिता वर्मा, उर्वशी बंछोर, गूँजेश्वरी बणछोर, विमला साहू, केंवरा साहू, खेमिन, सुरेखा साहू, श्रीराम टोली के सदस्य खेमिन साहू पूर्व सरपंच, रमेश देवांगन, टामनलाल साहू, सुनीता ठाकुर, ललिता बनपेला, योगेश्वरी साहू , ललिता वर्मा उपस्थित रहे।

किडनी की सेहत के प्रति जागरूक होना जरूरी ङ्क डॉ.मीना पटेल (नेफ्रोलॉजिस्ट)

सारँगढ (समय दर्शन)। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ.मीना पटेल ने लोगों से किडनी की सेहत के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज के समय में बदलती जीवनशैली,अनियमित खान पान,बढ़ता ब्लड प्रेशर और डायबिटीज किडनी रोग के सबसे बड़े कारण बनते जा रहे हैं। अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ सकता है।

डॉ.मीना पटेल ने बताया कि किडनी हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है,जो खून को साफकरने,शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने और शरीर में पानी व खनिजों का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। किडनी के खराब होने पर शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें सूजन,थकान,भूख कम लगना,उल्टी, पेशाब में बदलाव और हाई ब्लड प्रेशर शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि कई बार किडनी की बीमारी शुरूआती चरण में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बढ़ती रहती है,इसलिए नियमित जांच बहुत जरूरी है। खासकर जिन लोगों को डायबिटीज,हाई ब्लड प्रेशर,मोटापा या परिवार में किडनी रोग का इतिहास है,उन्हें समय समय पर किडनी की जांच जरूर करानी चाहिए। डॉ.पटेल के अनुसार किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना,संतुलित आहार लेना,नमक का सेवन कम करना,धूम्रपान और शराब से दूर रहना,नियमित व्यायाम करना और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का सेवन न करना बेहद जरूरी है। विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य लोगों को किडनी से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना और समय पर जांच व उपचार के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर डॉ.मीना पटेल ने संदेश दिया कि अगर हम अपनी जीवनशैली में थोड़े से बदलाव करें और नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें,तो किडनी की गंभीर बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है।

टी.एल.एम. मेले से शिक्षण को मिला नया आयाम

पिथौरा(समय दर्शन)। पिथौरा विकास खण्ड अंतर्गत संकुल केंद्र गड़बेड़ा में संकुल स्तर पर शिक्षण को अधिक प्रभावी और गतिविधि आधारित बनाने के उद्देश्य से टी.एल.एम.मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संकुल के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने छात्रों के साथ अपने-अपने नवाचारों एवं शिक्षण सामग्रियों का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के दौरान संकुल प्राचार्य श्री के. के. साहू ने आओ करके सीखें की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि जब बच्चे किसी विषय को स्वयं प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से समझते हैं, तो वह ज्ञान उनके मन में लंबे समय तक स्थायी रहता है।इस दौरान संकुल समन्वयक लोकनाथ सिन्हा ने टी.एल.एम. मेले के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षकों को नवाचारों को साझा करने और एक-दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे शिक्षण पद्धति में रचनात्मकता बढ़ती है और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई अधिक रोचक बनती है। कार्यक्रम में शिक्षक हेमंत खुटे ने कहा कि टी.एल.एम. के माध्यम से विद्यार्थियों को किसी भी विषय के कॉन्सेप्ट को समझने में काफी मदद मिलती है। जब पढ़ाई को मॉडल, चार्ट, खेल और गतिविधियों से जोड़ा जाता है, तो कठिन विषय भी सरल और समझनेयोग्य बन जाते हैं।

इस अवसर पर गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित अनेक आकर्षक और उपयोगी शिक्षण सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि गतिविधि आधारित शिक्षा से विद्यार्थियों में सीखने की रुचि बढ़ती है और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।उक्त मेले में अपने - अपने विद्यालयों से दो ङ्क दो विद्यार्थियों के साथ दयाराम पेटल (प्रधान पाठक) हेमंत खुटे, विवेक दीक्षित, नरेन्द्र कुमार दीवान (प्रधानपाठक) हितेश पटेल (प्रधान पाठक) बेदराम सिन्हा (प्रधानपाठक) लक्ष्मी पटेल (सहा शिक्षक) तेजुराम यादव (प्रधानाचार्य) ने सहभागिता की थी । सहायक शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन के आधार पर शासकीय मिडिल स्कूल पोटापारा को प्रथम स्थान, मिडिल स्कूल कसहीबाहरा को दूसरा तथा शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल गड़बेड़ा को तीसरा स्थान मिला। मेले में शिरकत सभी छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित छात्र छात्राओं में भुवन लाल ध्रुव, वीर कुमार, नीरज साहू, तारिणी ठाकुर, करण पटेल, यामिनी साहू, छोटी वस्त्राकर, ललिता ध्रुव, मोहनीश दीवान, काव्या ध्रुव, खुशी ध्रुव, विकास यादव, राहुल ध्रुव, रूबी निषाद, साक्षी ठाकुर, लक्ष्मी साहू, जागृति सेन, सिद्धार्थ निषाद, घनश्याम ध्रुव का नाम शामिल है। कार्यक्रम का संचालन शासकीय प्राथमिक शाला कसहीबाहारा के प्रधान पाठक हितेश पटेल ने तथा आभार प्रदर्शन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गड़बेड़ा के प्रधान पाठक दयाराम पटेल द्वारा किया गया।

मेले उपरांत आगामी 5 वीं व 8 वीं की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु प्रधान पाठकों की बैठक आहूत की गई जिसमें संकुल प्राचार्य के के साहू ने परीक्षा के कुशल संचालन हेतु आवश्यक दिशा ङ्क निर्देश दिए। इस दरमियान छात्रवृत्ति पूर्णता, अपार आई डी पूर्णता हेतु समीक्षा की गई साथ ही मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर जोर दिया गया।

भाजपा नेता की अवैध अफीम खेती पर कांग्रेस का तीखा हमला, सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल - लोचन यादव

दुर्ग (समय दर्शन)। दुर्ग जिले के ग्राम समौदा में भाजपा नेता विनायक ताम्रकर द्वारा की जा रही अवैध खेती के मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के सचिव लोचन यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और भाजपा सरकार के संरक्षण में अवैध गतिविधियां खुलेआम फल-फूल रही हैं। लोचन यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा के नेता ही यदि अवैध खेती और गैरकानूनी कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में लगभग 2 वर्षों से अवैध अफीम खेती का कारोबार चल रहा था, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस मामले को गंभीरता से उठा रही है और लगातार प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद ही प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। लोचन यादव ने जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष श्री राकेश ठाकुर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता और प्रमुखता के साथ उठाया तथा इसे जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूती से पहुंचाने का कार्य किया, जिसके कारण प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि राकेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आखिर भाजपा नेता को इतना संरक्षण किसके इशारे पर मिल रहा था? यदि प्रदेश की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफकड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वह कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में अवैध कारोबार, माफियागिरी और कानून की अनदेखी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता में भय और असंतोष का माहौल बन रहा है। कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेगी और यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चोवाराम साहू किसान प्रकोष्ठ के संयोजक बने

कवर्धा (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ (पंजीयन संख्या 33/61) ने एकीकृत नियमावली के अंतर्गत नए प्रकोष्ठों का गठन कर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इस नए प्रकोष्ठ गठन में कबीरधाम जिले को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी क्रम में जिले के युवा और सक्रिय नेता चोवाराम साहू को संयोजक, किसान प्रकोष्ठ के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री साहू की नियुक्ति से समाज में हर्ष है।

चोवाराम साहू विकासखंड स. लोहारा के ग्राम रक्से के निवासी हैं और एक किसान परिवार से ताल्लुख रखते हैं। इसके अलावा श्री साहू पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश साहू संघ युवा प्रकोष्ठ तथा पूर्व अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ जिला साहू संघ कबीरधाम रह चुके हैं। समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी, किसानों के बीच उनकी मजबूत पकड़ और सकारात्मक योगदान को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। इस नियुक्ति के बाद क्षेत्र के साहू समाज और किसान समुदाय में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई है। समाज के लोगों ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नियुक्ति के बाद चोवाराम साहू ने कहा, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, मैं उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाऊँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि समाज और किसान हित में हर संभव योगदान दिया जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की यह पहल जिले के किसानों और युवा नेताओं के लिए प्रेरणास्रोत बनी है और इसके माध्यम से समाज में नई सक्रियता और संगठनात्मक ताकत आने की संभावना जताई गई है।

बसना का गौरव पथ:3 किलोमीटर में अनेक क्रॉसिंग, जहाँ हर मोड़ पर मौत का खतरा

बसना (समय दर्शन)। बसना में अरेकेल बाईपास से सराईपाली बाईपास तक निर्मित गौरव पथ अब स्थानीय निवासियों के लिए जान का खतरा बन चुका है। यह लगभग 3 किलोमीटर लंबा मार्ग पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसके डिवाइडर पर बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल के मनमाने ढंग से बनाए गए 30 के आसपास क्रॉसिंग अब सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन गए हैं।

समस्या की मुख्य वजहें

अनियमित क्रॉसिंग: ठेकेदार द्वारा हर 100-200 मीटर की दूरी पर डिवाइडर में क्रॉसिंग बनाए गए हैं, जो नियमों की अनदेखी को दर्शाते हैं।

दृश्यता की कमी: डिवाइडर की ऊंचाई और लगाए गए पेड़-पौधों के कारण आने-जाने वाले वाहनों को क्रॉस करने वाले पैदल यात्रियों या वाहनों को देख पाना मुश्किल हो जाता है। सिग्नल की अनुपस्थिति: किसी भी क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट या साइन बोर्ड नहीं हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है।

दुर्घटनाओं का आंकड़ा

स्थानीय निवासियों के अनुसार, पिछले तीन महीनों में लगभग 150 सड़क दुर्घटना के मामले बसना थाने में दर्ज हुए हैं। दर्ज न होने वाले मामलों को मिलाकर औसतन हर महीने 70-80 दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है।

जिम्मेदारी का सवाल

नागरिकों का सवाल है कि इन हादसों की जिम्मेदारी किसकी है—शासन-प्रशासन, अधिकारी-कर्मचारी या ठेकेदार? निर्माण के दौरान गुणवत्ता, नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप पहले से लगते रहे हैं, और अब इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद मनोज गहेरवाल ने बताया कि वार्ड को जोड़ने वाले इन क्रॉसिंग से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने नगर पंचायत के सीएमओ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो दुर्घटनाओं के आंकड़े और बढ़ेंगे। वही नगर पंचायत बसना के उपाध्यक्ष शीत गुप्ता का कहना है कि नगर के गौरव पथ निर्माण कार्य मे अनावश्यक क्रासिंग निर्माण किया गया है जिसके कारण नगर में दुर्घटनाएं बढ़ गयी है मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कहा गया है जल्द ही अनावश्यक क्रासिंग को बंद किया जाए। यह मुद्दा बसना में आम चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन से अपेक्षा है कि क्रॉसिंग पर सिग्नल लगाना, डिवाइडर की ऊंचाई समायोजित करना और अन्य सुरक्षा उपाय तुरंत लागू किए जाएं ताकि नागरिकों में जन हानि को बचाई जा सके।

झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बने अभिमन्यु जायसवाल

अंतिम व्यक्ति तक योजनाएँ पहुँचाने पर रहेगा विशेष फोकस-अभिमन्यु

बसना (समय दर्शन)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय एवं जिला अध्यक्ष एतराम साहू के निर्देशन व मार्गदर्शन में भाजपा संगठन लगातार समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुँच मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के रूप में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अभिमन्यु जायसवाल की नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है तथा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले जरूरतमंद एवं वंचित वर्ग के लोगों तक शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। प्रकोष्ठ के माध्यम से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, राशन व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित कराने का कार्य किया जाता है। साथ ही बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को संगठन और शासन तक पहुँचाकर उनके समाधान की

दिशा में सक्रिय पहल भी की जाती है। अभिमन्यु जायसवाल की नियुक्ति से अब इन क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अभिमन्यु जायसवाल लंबे समय से भाजपा संगठन के सक्रिय एवं जमीनी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष, नगर पंचायत बसना के पूर्व उपाध्यक्ष तथा भाजपा मंडल बसना के महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यालय प्रभारी के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संगठन को मजबूती प्रदान की है। उनकी सक्रियता और संगठनात्मक क्षमता के कारण बसना मंडल एवं शहर क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिली है।

उनकी इस नियुक्ति पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय, सांसद रूपकुमारी चौधरी,जिला अध्यक्ष एतराम साहू, विधायक योगेश्वर राजु सिन्हा बसना विधायक डॉ. संपत अग्रवाल, वरिष्ठ जिला महामंत्री जितेंद्र त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पटेल,कृष्ण कुमार साहू,भाजपा नेता डॉ. एन.के. अग्रवाल,रमेश अग्रवाल,अनिल अग्रवाल,युवा मोर्चा जिला महामंत्री कामेश बंजारा,नगर पंचायत अध्यक्ष डॉ. खुशबू अग्रवाल,नगर पंचायत उपाध्यक्ष शीत गुप्ता,जनपद उपाध्यक्ष मोहित पटेल,भाजपा मंडल अध्यक्ष बसना नरेंद्र यादव, महामंत्री दीपक शर्मा,सरोज पटेल,अमृत चौधरी,प्रकाश सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

स्वामित्वधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक रोहित खड़तकर द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ग्राम छाटा, पोस्ट देवादा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) 491111 से मुद्रित कर बी-4, प्रेस काम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट, दुर्ग छ.ग. 491001 से प्रकाशित। संपादक :- रोहित खड़तकर,
समाचार संपादक : दामोदर राव, फोन नं.-0788-4051213, मो. 9827104452, रायपुर कार्यालय:-0771-4218364, ईमेल - samay.darshan191@gmail.com पं. क्र. CHHHIN/2011/41517 डाक पंजीयन क्रमांक छ.ग./दुर्ग/61/2024-26